घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 292- सोमवार 24- अगस्त 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

घी में मिलावट करने वालों पर गिरी गाज

एफएसएसएआई ने तीन ब्रांडों की बिक्री पर लगाई रोक,दिल्ली की ये कंपनी भी नपी

नई दिल्ली,23 अगस्त 2026। खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर प्राधिकरण ने दो कंपनियों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। एक का लाइसेंस निलंबित हुआ है, जबकि दूसरी कंपनी के सभी घी उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। आखिर जांच में ऐसी कौन सी गड़बड़ियां मिलीं,जिनके बाद यह कार्रवाई करनी पड़ी? भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य सुरक्षा नियमों के गंभीर उल्लंघन के मामले में दो कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की है। नई दिल्ली की मार्शे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है। वहीं, दमन की एसडीपी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को अपने सभी प्रकार के घी की बिक्री तुरंत बंद करने का आदेश दिया गया है। प्राधिकरण ने रविवार को बताया कि दोनों कंपनियों के प्रतिष्ठानों की जांच और उसके बाद की पड़ताल में गंभीर खाद्य सुरक्षा संबंधी उल्लंघन सामने आए। इसके बाद मार्शे रिटेल का लाइसेंस निलंबित किया गया और एसडीपी इंडस्ट्रीज के घी उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी गई। प्राधिकरण के अनुसार,मार्शे रिटेल के प्रतिष्ठान की जांच में कई कमियां मिलीं। इनमें प्रतिष्ठान की बनावट,कामकाज की व्यवस्था, साफ-सफाई और कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता से जुड़ी खामियां शामिल थीं। खाद्य पदार्थों को संभालने वाले कर्मचारियों के प्रशिक्षण और जरूरी अभिलेख रखने में भी कमी पाई गई। इन कमियों के बाद कंपनी को खाद्य कारोबार की सभी गतिविधियां बंद करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, पाई गई खामियों को दूर करने के लिए कहा गया है। कंपनी का लाइसेंस 30 दिनों के लिए निलंबित रहेगा।

मुंबई में 22 फीट ऊंची भगवान गणेश की मूर्ति गिरी,2 लोगों की मौत और 5 घायल

मुंबई,23 अगस्त 2026। गणेशोत्सव की तैयारियों के बीच मुंबई के भुलेश्वर में बड़ा हादसा हो गया। शनिवार रात'भुलेश्वर चा राजा'के नाम से मशहूर भगवान गणेश की 22 फीट ऊंची मूर्ति लाते समय संतुलन बिगड़ने के कारण गिर गई। मूर्ति की चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गई और पांच अन्य घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक, देर रात भायखला से भुलेश्वर ले जाई जा रही 22 फुट ऊंची विशाल मूर्ति मंडप से 50-60 मीटर पहले अचानक गिर गई। मूर्ति की चपेट में आने से करीब 7 लोग घायल हो गए। हादसे की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम, बीएमसी के अधिकारी और मुंबई पुलिस मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू करके घायलों को नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया गया अस्पताल में भुलेश्वर में गणपति मंडल के अध्यक्ष समेत दो को मृत घोषित कर दिया गया। मृतकों की पहचान 33 वर्षीय संकेत नेवशे और 30 वर्षीय बृजेश हेमंत जोशी के रूप में हुई है। वहीं, वैभव घेनांद (38),पवन चौरसिया (25),लावण्या गनेर (5),दिव्या गनेर (7) और कुणाल काशिद (26) घायल हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। गौरतलब है कि मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में गणेशोत्सव बहुत भव्य तरीके से मनाया जाता है। अगले महीने पड़ने वाले गणेश चतुर्थी की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। दस दिन चलने वाले इस त्योहार में घरों के साथ सार्वजनिक पंडालों में गणेश प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं। मुंबई में प्रतिमाओं को पंडाल तक लाने और विसर्जन के लिए जुलूस निकाले जाते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं।

मंत्री केदार कश्यप के काफिले की गाड़ियों को कोंडागांव सीमा पर इनोवा ने मारी टक्कर,हादसों में 4 जवान घायल

रायपुर,23 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ के वन एवं सहकारिता मंत्री केदार कश्यप के काफिले में शामिल फॉलो वाहन रविवार को जगदलपुर-कोंडागांव सीमा पर सड़क हादसे का शिकार हो गए। भानपुरी के पास नेशनल हाईवे पर एक अनियंत्रित इनोवा वाहन ने काफिले में पीछे चल रही दो गाड़ियों को तेज टक्कर मार दी। अचानक हुई इस टक्कर के बाद हाईवे पर चीख-पुकार और अफरा-तफरी का माहौल निर्मित हो गया। इनोवा की जोरदार टक्कर से काफिले के फॉलो वाहनों में सवार 4 सुरक्षा जवान घायल हो गए। हादसे के तुरंत बाद मौके पर मौजूद अन्य सुरक्षाकर्मियों और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को संभाला गया। प्राथमिक राहत के बाद घायल जवानों को तत्काल कोंडागांव जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची और यातायात को व्यवस्थित कराया। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाया जा रहा है कि दुर्घटना इनोवा चालक की लापरवाही या तेज रफ्तार की वजह से हुई।

रॉकेट से सैटेलाइट तक...पीएम मोदी ने 20 स्पेस स्टार्टअप्स के सीईओ से की मुलाकात

स्टार्टअप्स को भरोसा दिलाते हुए प्रधानमंत्री बोले...

'कोई मेरा हाथ नहीं छोड़ देगा ये विश्वास पैदा कर रहे'

नई दिल्ली,23 अगस्त 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के सीईओ और संस्थापकों से मुलाकात की। बैठक में भारत के तेजी से बढ़ते निजी अंतरिक्ष क्षेत्र,नई तकनीक,नवाचार और देश को वैश्विक अंतरिक्ष नेतृत्व की दिशा में आगे ले जाने की संभावनाओं पर चर्चा हुई। बैठक में स्काईरूट एयरोस्पेस,अग्निकुल कॉसमॉस,पिक्सल,ध्रुव स्पेस,गैलेक्सआई, पियरसाइट,बेलाट्रिक्स एयरोस्पेस,दिगंतारा और सैटश्योर समेत 20 स्टार्टअप्स के प्रमुख शामिल हुए। इन कंपनियों का काम रॉकेट,सैटेलाइट,पृथ्वी अवलोकन,स्पेस डेटा और अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता जैसी तकनीकों से जुड़ा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले दिनों अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप से जुड़े युवा नेतृत्वकर्ताओं से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार इस प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है कि उन्हें लगे की कोई उनका हाथ नहीं छोड़ देगा। प्रधानमंत्री के आवास पर इस संवाद का रविवार को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर वीडियो जारी किया गया। प्रधानमंत्री ने युवा स्टार्टअप नेतृत्वकर्ताओं से कहा कि आपने एक नए क्षेत्र में साहस दिखाया है। सबसे बड़ी बात है कि आपने सरकार की बात पे भरोसा किया। वीडियो साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा,'भारत के कुछ सबसे प्रतिभाशाली अंतरिक्ष स्टार्टअप्स से मुलाकात हुई। हमेशा की तरह,उनकी ऊर्जा और महत्वाकांक्षा से मैं बहुत प्रभावित हुआ। आपको उनकी दूरदर्शिता और आशावादिता बहुत पसंद आएगी। मुझे बताइए...भारत की अंतरिक्ष यात्रा में आपको सबसे ज्यादा क्या उत्साहित करता है? 'वीडियो में प्रधानमंत्री स्टार्टअप से कहते हैं,'मेरा एक मत रहा कि जो भी हम निर्णय करें,हम उसमें कंसिस्टेंट रहे। हम बार-बार उसमें बदलाव ना करें ताकि कोई भी रिस्क लेना चाहता है तो उसको भरोसा रहे कि मेरी गलती के कारण कुछ गड़बड़ होगा तो ठीक है लेकिन कोई मेरा हाथ नहीं छोड़ देगा ।

स्काईरूट का हर महीने रॉकेट लॉन्च करने का लक्ष्य

स्काईरूट ने पीएम मोदी को बताया कि 18 जुलाई को भारत के पहले प्राइवेट रॉकेट से सैटेलाइट्स को कामयाबी के साथ ऑर्बिट में स्थापित किया था। कंपनी ने अब तक 3 फैक्ट्रियां तैयार कर ली हैं,जिनमें हर महीने एक रॉकेट बनाने की क्षमता है। कंपनी की योजना हर महीने एक रॉकेट लॉन्च करने की है। इसके बाद का लक्ष्य हर हफ्ते एक और भविष्य में हर दिन कई रॉकेट लॉन्च करने का है।

1 महीने में मिले 8 नए इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स

भारतीय स्टार्टअप्स ग्लोबल लेवल पर ग्राउंड स्टेशन नेटवर्क तैयार कर रहे हैं और सैटेलाइट इंजनों का एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। यह इंजन सैटेलाइट्स को स्पेस में 5 से 15 सालों तक एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करते हैं। कॉस्ट-इफेक्टिवनेस यानी कम लागत और टैलेंट के दम पर भारतीय कंपनियों को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।

ग्लोबल स्पेस लीडरशिप पर जोर...

राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2026 के अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती वैश्विक भूमिका को रेखांकित किया था। उन्होंने कहा था कि भारत का निजी अंतरिक्ष क्षेत्र दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है और देश का स्पेस सेक्टर वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में अंतरिक्ष क्षेत्र की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है।

युवाओं की तकनीकी क्षमता की सराहना

प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं और नई पीढ़ी के वैज्ञानिकों व इंजीनियरों की क्षमता की भी सराहना की। उन्होंने कहा था कि आज भारत के युवा प्रोपल्शन सिस्टम,कंपोजिट मटेरियल,रॉकेट स्टेज और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म जैसी अत्याधुनिक तकनीकों पर काम कर रहे हैं। इन क्षेत्रों में हो रहा नवाचार भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं को नई दिशा दे रहा है।

चंद्रयान-3 से बढ़ा आत्मविश्वास

चंद्रयान-3 की सफलता ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को वैश्विक पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाई। 2023 में मिशन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफल सॉफ्ट लैंडिंग की थी। इसके बाद मिशन से मिले वैज्ञानिक आंकड़े दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए उपलब्ध कराए गए।

गिरिडीह-हजारीबाग में 28 नामजद,900 अज्ञात पर एफआईआर,पुलिस-छात्र झड़प के बाद बड़ा एक्शन

नई दिल्ली,23 अगस्त 2026। झारखंड में सरकारी नौकरियों और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच हुई झड़प के बाद अब पुलिस कार्रवाई भी बढ़ गई है। गिरिडीह और हजारीबाग में प्रदर्शन से जुड़े मामलों में कुल 28 नामजद और करीब 900 अज्ञात लोगों के खिलाफ तीन एफ आई आर दर्ज की गई हैं।

इससे पहले रांची में भी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले दर्ज किए जा चुके हैं। अधिकारियों के मुताबिक,गिरिडीह में शुक्रवार और शनिवार को प्रदर्शन के दौरान हुई झड़पों को लेकर टाउन पुलिस स्टेशन में दो अलग-अलग एफ आईआर दर्ज की गई। पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिस के साथ विवाद की घटनाओं को आधार बनाकर कार्रवाई की है। मामले में 28 लोगों को नामजद किया गया है,जबकि बड़ी संख्या में अज्ञात प्रदर्शनकारियों को भी आरोपी बनाया गया है।

सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप : पुलिस के अनुसार,रांची में दर्ज तीन मामलों में से एक एफआईआर पुलिस की शिकायत पर दर्ज की गई है। इसमें प्रदर्शनकारियों पर सरकारी काम में बाधा डालने और निर्धारित रूट चार्ट के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप लगाए गए हैं। वहीं, अन्य दो एफआईआर अलग-अलग लोगों की शिकायतों के आधार पर दर्ज की गई हैं। पुलिस का कहना है कि पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है।

हजारीबाग में भी पुलिस से झड़प का मामला

हजारीबाग में भी प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ कथित मारपीट और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में एक एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में करीब 900 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस अब प्रदर्शन से जुड़े वीडियो,मौके पर मौजूद लोगों और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है।

रांची में पहले ही दर्ज हो चुकी हैं तीन एफआईआर

गिरिडीह और हजारीबाग से पहले रांची में भी छात्रों के प्रदर्शन को लेकर तीन एफआईआर दर्ज की गई थीं। कोतवाली थाना क्षेत्र में दर्ज इन मामलों में 14 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया,जबकि 200 से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। रांची सिटी एसपी पारस राणा ने इन एफआईआर की जानकारी दी थी।

बांग्लादेश-हिंदू परिवार के 4 लोगों की संदिग्ध हालात में मौत

बंद घर से रिटायर्ड शिक्षक,पत्नी-बच्चों के शव मिले

ढाका,23 अगस्त 2026। बांग्लादेश के रंगपुर शहर में एक हिंदू परिवार के चार लोग संदिग्ध हालात में मृत मिले हैं। इनमें रिटायर्ड स्कूल शिक्षक,उनकी पत्नी, बेटी और बेटा शामिल हैं। चारों के शव एक बंद घर से मिले। पुलिस, सीआईडी और डिटेक्टिव ब्रांच ने जांच शुरू कर दी है। मृतकों की पहचान गणपति चक्रवर्ती (65), पत्नी प्रीतिलता चक्रवर्ती (50), बेटी आगमी चक्रवर्ती प्रार्थी (23) और बेटे प्रियम चक्रवर्ती (12) के रूप में हुई है। गणपति रंगपुर जिला स्कूल में शिक्षक थे और पिछले साल 31 दिसंबर को रिटायर हुए थे। रिटायरमेंट के बाद वे होम्योपैथी का काम भी कर रहे थे। परिजन के मुताबिक,प्रीतिलता की छोटी बहन पूजा चक्रवर्ती ने उनसे गुरुवार दोपहर आखिरी बार बात की थी। इसके बाद गुरुवार रात से परिवार के चारों मोबाइल फोन बंद हो गए। शनिवार रात परिजन रंगपुर के दासपाड़ा इलाके में उनके घर पहुंचे। घर का मुख्य गेट बंद था और अंदर की सभी लाइटें भी बंद थीं। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने घर का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और चारों के शव बरामद किए। रंगपुर मेट्रोपॉलिटन सीआईडी के अधिकारी सुबीर चौधरी के मुताबिक,गणपति का शव छत पर, उनकी पत्नी और बेटी के शव सीढ़ियों के पास मिले।

मेडिकल सीट पाने के बाद भी हो सकता है एडमिशन कैंसिल,छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी की बड़ी चेतावनी

रायपुर,23 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ में NEET UG Counselling 2026 के दौरान स्थानीय विद्यार्थियों के हितों की अनदेखी नहीं होगी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि डोमिसाइल या दस्तावेजों को लेकर किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर गंभीरता से जांच की जाएगी। वहीं राज्य काउंसलिंग समिति ने स्पष्ट किया है कि मूल दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही प्रवेश प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी। गलत जानकारी, तथ्य छिपाने या फर्जी दस्तावेज के आधार पर मिला प्रवेश नियमानुसार रद्द किया जा सकता है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि प्रदेश में मेडिकल कॉलेज और एमबीबीएस सीटें बढ़ाने का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के अधिक से अधिक बच्चों को मेडिकल शिक्षा का अवसर देना है। उन्होंने कहा कि स्थानीय विद्यार्थियों के हितों के साथ किसी भी तरह की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री ने कहा कि डोमिसाइल को लेकर यदि कोई शंका या शिकायत सामने आती है तो उसकी पूरी गंभीरता से जांच होगी। सही दस्तावेज रखने वाले विद्यार्थियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि, नियमों के उल्लंघन या फर्जीवाड़े का मामला सामने आने पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों ने मेहनत से यह अवसर हासिल किया है। ऐसे में उनके भविष्य और अधिकारों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। सीटें बढ़ाने के साथ यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि इसका लाभ पात्र विद्यार्थियों को ही मिले। छत्तीसगढ़ राज्य काउंसलिंग समिति के अनुसार NEET UG प्रवेश वर्ष 2026 की राज्य स्तरीय काउंसलिंग प्रक्रिया ऑनलाइन और निर्धारित प्रवेश नियमों के अनुसार की जा रही है। इसमें पंजीयन, प्राथमिकता क्रम, सीट आवंटन, मूल दस्तावेजों की संवीक्षा और प्रवेश की प्रक्रिया शामिल है। छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा स्नातक प्रवेश नियम, 2025 के नियम 7 के तहत अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच की जाएगी।

इस दौरान मूल निवासी प्रमाण-पत्र, श्रेणी या संवर्ग से जुड़े प्रमाण-पत्र और नियमानुसार आवश्यक अन्य दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। सीट आवंटित होने के बाद अभ्यर्थी के मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने और सत्यापन में पात्र पाए जाने पर ही प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी।

स्कूल से लौटते समय नदी में बहे 3 बच्चे,मौत

रायपुर में तेज बारिश,एनीकट से गिरा युवक,बिजली गिरने से दंपती की गई जान

रायपुर,23 अगस्त 2026। रायपुर में रविवार दोपहर से तेज बारिश हुई। वहीं बिलासपुर जिले में स्कूल से घर लौट रहे 3 बच्चे घोंघा नदी के तेज बहाव की बह गए। तीनों बच्चों के शव बरामद कर लिए गए। ग्राम समडील निवासी आशुतोष जायसवाल और विजय जायसवाल ने अपनी बेटी रिद्धी (8) और सिद्धी (8) का दाखिला गांव से 2 किलोमीटर दूर नयापारा स्थित डीपी विप्र स्कूल में कराया था। शनिवार को दोनों बहनें स्कूल गई थीं। शाम 4 बजे छुट्टी होने पर उन्हें लेने के लिए आशुतोष का बड़ा बेटा अनमोल जायसवाल (7) साइकिल से स्कूल गया था। स्कूल से लौटते समय बच्चे पुल की जगह घोंघा नदी के रास्ते से घर लौट रहे थे। नदी के बीच पहुंचने पर अनमोल तेज बहाव में साइकिल संभाल नहीं पाया। इसके बाद साइकिल पर बैठी रिद्धी और सिद्धी समेत तीनों बच्चे पानी में बह गए। वहीं बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में एक युवक कन्हर नदी में एनीकट पार करते समय तेज बहाव में बह गया। यह घटना रविवार सुबह करीब 9 बजे हुई,जब एनीकट के ऊपर से पानी बह रहा था। युवक झारखंड के गोदरमाना से छत्तीसगढ़ की ओर आ रहा था। युवक की तलाश की जा रही है। इसके अलावा गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के कटरा ढपनीपानी गांव में बिजली गिरने से एक बैगा दंपती की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मंगल सिंह पत्नी बिरस्पतिया बाई के साथ घर पर थे। तेज गड़गड़ाहट और मूसलाधार बारिश के दौरान उनके मकान पर बिजली गिरी। पति-पत्नी आंगन में ही बेहोश हो गए। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने 108 संजीवनी एक्सप्रेस की मदद से दंपती को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) मरवाही पहुंचाया। डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटना मरवाही थाना क्षेत्र की है।

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में नदी नाले उफान पर : गौरेला-पेंड्रा-मरवाही क्षेत्र में लगातार तेज बारिश के कारण कई नाले उफान पर आ गए। बस्ती-बगरा मुख्य मार्ग पर स्थित कलेवा नाला में तेज बहाव के कारण पुल पर पानी भर गया। इससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। कई लोगों को जान जोखिम में डालकर पुल पार करते देखा गया,जबकि अनेक यात्री घंटों फंसे रहे। कोटमी खुर्द-उमरखोही कच्चा मार्ग भी जलमग्न होने से ग्रामीणों को परेशानी हुई। हालांकि, बारिश कम होने के बाद यातायात धीरे-धीरे सामान्य हो गया।

अगले 7 दिन बारिश का अलर्ट

छत्तीसगढ़ में अगले 7 दिनों तक बारिश की गतिविधियां बनी रहने की संभावना है। अगले 24 घंटे में उत्तर बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम बन रहा है। इसके असर से आने वाले दिनों में प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। शनिवार को रायपुर में सुबह से रुक-रुककर तेज बारिश हो रही है। तेज बारिश से सुंदरनगर इलाके में महादेवघाट रोड पर जलभराव हो गया है। प्रदेश में 1 जून से अब तक हुई मौसमी बारिश सामान्य श्रेणी में है। हालांकि, सामान्य से 8% कम बारिश दर्ज की गई है।

सावन में शिवभक्ति में डूबा रायपुर

सीएम विष्णुदेव साय ने किया रुद्राभिषेक,हजारों कांवड़िए हटकेश्वरनाथ महादेव के लिए रवाना

रायपुर,23 अगस्त 2026। पवित्र श्रावण मास के अवसर पर राजधानी रायपुर शिवभक्ति में सराबोर नजर आई। गुढ़ियारी स्थित मारुति मंगलम परिसर में आयोजित भव्य कांवड़ यात्रा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। उन्होंने विधि-विधान से भगवान शिव का रुद्राभिषेक और पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री साय ने कांवड़ यात्रा में शामिल शिवभक्तों का उत्साह बढ़ाते हुए उन्हें सावन की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि सावन का महीना भगवान शिव की आराधना और भक्ति का विशेष अवसर है। कांवड़ यात्रा आस्था, भक्ति और समर्पण की अनुपम अभिव्यक्ति है। मारुति मंगलम परिसर से हजारों कांवड़िए पवित्र जल लेकर महादेव घाट स्थित भगवान हटकेश्वरनाथ महादेव के जलाभिषेक के लिए रवाना हुए। शिवभक्तों के जयघोष और भक्ति गीतों से पूरा वातावरण शिवमय हो गया। सीएम साय ने कहा कि कांवड़ यात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहीं,बल्कि संस्कृति, परंपरा और सामाजिक समरसता का उत्सव भी है। ऐसे आयोजन समाज के विभिन्न वर्गों को एक साथ जोड़ते हैं और आपसी सद्भाव को मजबूत करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की पहचान उसकी प्राकृतिक सुंदरता और लोक-संस्कृति के साथ-साथ समृद्ध आध्यात्मिक परंपराओं से भी है। प्रदेश के प्राचीन शिवधाम और धार्मिक स्थल हमारी सांस्कृतिक विरासत के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा जैसे आयोजन नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति, परंपराओं और संस्कारों से जोड़ने का माध्यम हैं। राज्य सरकार प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं आध्यात्मिक स्थलों के विकास और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं के विस्तार की दिशा में लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भगवान भोलेनाथ से छत्तीसगढ़ की निरंतर प्रगति और प्रदेशवासियों के कल्याण की प्रार्थना की।

संपादकीय

जब अफसर की सख्ती से खाने की थाली तक बदलने लगे रंग

तुकाराम मुंढे का 'FDA मॉडल' बना चर्चा का विषय,लेकिन असली चुनौती कार्रवाई से आगे जाकर व्यवस्था को स्थायी रूप से बदलने की खाना हमारी जिंदगी की सबसे बुनियादी जरूरत है। लेकिन जिस चीज के बिना जीवन संभव नहीं, उसी भोजन की गुणवत्ता को लेकर हमारा समाज अक्सर सबसे ज्यादा लापरवाह दिखाई देता है। चमचमाते होटल हों या सड़क किनारे का ठेला,बड़े ब्रांड हों या छोटी दुकान–ग्राहक के सामने परोसी गई थाली के पीछे क्या कहानी है,यह सवाल अक्सर प्लेट आने के बाद नहीं, बीमारी होने के बाद पूछा जाता है।

यही वह जगह है जहां महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर तुकाराम मुंढे की कार्यशैली ने एक अलग बहस खड़ी कर दी है। पद संभालने के बाद उनकी कार्रवाई ने यह संदेश जरूर दिया है कि खाद्य सुरक्षा कोई कागजी खानापूर्ति नहीं,बल्कि सीधे नागरिकों के स्वास्थ्य से जुड़ा विषय है। महाराष्ट्र FDA की आधिकारिक जानकारी के अनुसार मुंढे वर्तमान में विभाग के कमिश्नर हैं और विभाग का घोषित उद्देश्य खाद्य पदार्थों,दवाओं और कॉस्मेटिक्स की सुरक्षा एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करना है।

लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा केवल छापे और कार्रवाई नहीं हैं। दिलचस्प यह है कि कार्रवाई का असर रसोई से लेकर बाजार और स्कूल की कैंटीन तक दिखाई देने लगा है। मुंबई के कई स्कूलों में वड़ा-पाव और समोसे जैसे तले हुए खाद्य पदार्थों की जगह इडली, डोसा, पोहा और उपमा जैसे विकल्प आने लगे हैं। एयरेटेड ड्रिंक्स को भी हटाया गया है। यह बदलाव स्त्रष्ठ की स्कूलों में जंक फूड के खिलाफ कार्रवाई के बाद सामने आया है।

यानी सरकारी आदेश का असर केवल फाइल में नहीं,बच्चों की प्लेट में दिखाई दे रहा है। यही किसी प्रशासनिक कार्रवाई की सबसे बड़ी सफलता हो सकती है।

डर का असर या जिम्मेदारी का एहसास?

खाद्य कारोबार में निरीक्षण का उद्देश्य केवल दुकानदार को डराना नहीं होना चाहिए। असली उद्देश्य यह होना चाहिए कि व्यापारी निरीक्षक के आने का इंतजार न करे,बल्कि उसके आने की जरूरत ही न पड़े। अगर किसी होटल की रसोई केवल निरीक्षण की खबर सुनकर साफ हो जाती है,तो सवाल यह भी है कि वह पहले साफ क्यों नहीं थी?

अगर इस्तेमाल होने वाला तेल बार-बार गर्म करने की आदत कार्रवाई के बाद बदलती है,तो स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदारी पहले क्यों नहीं आई?

अगर स्कूल कैंटीन में बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर मेन्यू बदला जा सकता है,तो यह बदलाव किसी आदेश के बाद ही क्यों हुआ?

इसलिए तुकाराम मुंढे की सख्ती का सबसे बड़ा मूल्यांकन इस बात से नहीं होना चाहिए कि कितने छापे पड़े और कितने लाइसेंस निलंबित हुए। असली सवाल यह होना चाहिए कि कितने खाद्य कारोबारियों ने अपनी कार्यसंस्कृति बदली?

बड़े नाम भी कार्रवाई से बाहर नहीं...

इस अभियान की खासियत यह है कि कार्रवाई केवल छोटे दुकानदारों तक सीमित दिखाई नहीं देती। हालिया रिपोर्टों में बड़े रेस्तरां,होटल,क्विक-कॉमर्स वेयरहाउस और अंतरराष्ट्रीय फूड चेन के आउटलेट तक जांच के दायरे में आए हैं। महाराष्ट्र FDA की कार्रवाई में चार Domino's और एक Pizza Hut आउटलेट बंद किए जाने की रिपोर्ट सामने आई, जबकि अलग अभियान में 86 प्रतिष्ठानों की जांच के बाद 12 वेयरहाउस के परमिट निलंबित किए गए और 60 सुधार नोटिस जारी किए गए।

यही संदेश महत्वपूर्ण है...

खाद्य सुरक्षा में ब्रांड बड़ा नहीं होता,मानक बड़ा होता है। ग्राहक को यह भरोसा होना चाहिए कि वह पांच सितारा होटल में खा रहा हो या सड़क किनारे के छोटे भोजनालय में,न्यूनतम स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा के नियम सब पर समान रूप से लागू होंगे।

स्कूल की कैंटीन से शुरू हुई बड़ी लड़ाई

बच्चों के भोजन को लेकर महाराष्ट्र FDA का रुख विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। विभाग ने स्कूलों में सुरक्षित, स्वच्छ और संतुलित भोजन सुनिश्चित करने के लिए 2020 के खाद्य सुरक्षा नियमों के क्रियान्वयन का राज्यव्यापी आदेश भी जारी किया है।

स्कूल की कैंटीन में क्या बिकता है,यह मामूली मुद्दा नहीं है। बच्चा जिस भोजन को रोज खाता है,वही उसकी आदत बनता है और आदत आगे चलकर स्वास्थ्य को प्रभावित करती है।

इसलिए स्कूल के बाहर बिकने वाले खाद्य पदार्थों तक नियमन का विस्तार भी जरूरी है। रिपोर्टों के मुताबिक स्कूलों के आसपास 50 मीटर के दायरे में कुछ उच्च वसा,नमक और चीनी वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री, विज्ञापन और मुफ्त वितरण पर रोक की दिशा में कदम उठाए गए हैं।

लेकिन यहां भी एक सवाल है–नियम बनाना आसान है,उसका पालन कराना कठिन।

हर स्कूल के बाहर खड़े ठेले की निगरानी कौन करेगा? हर दुकान की नियमित जांच कौन करेगा? सीमित कर्मचारियों वाले FDA के सामने यह सबसे बड़ी चुनौती है।

सख्ती जरूरी है,लेकिन निष्पक्षता उससे भी जरूरी

तुकाराम मुंढे की कार्रवाई की चर्चा के बीच एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी सामने आई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक मामले में FDA को पुणे की एक मिठाई दुकान को ₹5 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया। रिपोर्ट के अनुसार फॉलो-अप निरीक्षण में दुकान ने 36 में से 35 खाद्य सुरक्षा मानकों का अनुपालन किया था,फिर भी लाइसेंस निलंबन जारी रखने पर अदालत ने सवाल उठाया।

यह घटना बताती है कि कठोर प्रशासन और मनमानी प्रशासन में फर्क होता है। नियम तोड़ने वाले के खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। लेकिन कार्रवाई भी कानून,प्रमाण और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होनी चाहिए। क्योंकि यदि ईमानदार कारोबारियों को भी अनावश्यक परेशानी होती है, तो सख्त कार्रवाई की विश्वसनीयता कमजोर पड़ सकती है।

इसलिए मुंढे मॉडल की अगली परीक्षा यही है–क्या सख्ती के साथ निष्पक्षता भी उतनी ही मजबूत रहेगी?

क्या यह मॉडल पूरे देश में लागू हो सकता है?

महाराष्ट्र की कहानी देश के बाकी राज्यों के लिए भी एक बड़ा सवाल छोड़ती है।

क्या हर राज्य का खाद्य एवं औषधि प्रशासन इसी तरह सक्रिय हो सकता है?

क्या जिला स्तर पर नियमित निरीक्षण हो सकते हैं?

क्या होटल और रेस्टोरेंट की स्वच्छता रिपोर्ट सार्वजनिक की जा सकती है?

क्या उपभोक्ता आसानी से शिकायत कर सकता है और शिकायत पर समयबद्ध कार्रवाई हो सकती है?

क्या स्कूलों और अस्पतालों की कैंटीन की नियमित जांच हो सकती है?

और क्या कार्रवाई केवल त्योहारों या किसी बड़े हादसे के बाद होने के बजाय पूरे साल चल सकती है?

यदि इन सवालों के जवाब 'हां' में मिलते हैं तो तुकाराम मुंढे की कार्यशैली किसी एक अधिकारी की कहानी नहीं रहेगी, बल्कि प्रशासनिक सुधार का उदाहरण बन सकती है।

मुंढे से ज्यादा जरूरी है 'मुंढे मॉडल'

व्यवस्था किसी एक अधिकारी के भरोसे नहीं चल सकती

आज तुकाराम मुंढे हैं,कल कोई दूसरा अधिकारी होगा। यदि कार्रवाई केवल अधिकारी की व्यक्तिगत सख्ती पर निर्भर है तो उसके तबादले के साथ व्यवस्था फिर पुराने ढर्रे पर लौट सकती है।

इसलिए जरूरत है कि व्यक्ति नहीं,व्यवस्था सख्त हो

निरीक्षण की डिजिटल निगरानी हो। खाद्य नमूनों की जांच समयबद्ध हो। दोषी प्रतिष्ठानों की जानकारी सार्वजनिक हो। लाइसेंस निलंबन और बहाली की प्रक्रिया पारदर्शी हो। उपभोक्ताओं की शिकायतों का रिकॉर्ड बने। और अधिकारियों की जवाबदेही भी तय हो।

तभी खाद्य सुरक्षा अभियान स्थायी बदलाव में बदलेगा।

क्योंकि असली सफलता यह नहीं कि दुकानदार अधिकारी से डरने लगे

असली सफलता तब होगी जब दुकानदार ग्राहक के स्वास्थ्य को लेकर खुद जिम्मेदार हो जाए।

आखिर सवाल हमारी थाली का है...

हम हर दिन भोजन खरीदते हैं, लेकिन उसके पीछे की स्वच्छता नहीं खरीद सकते। हम होटल में खाना खाते हैं, लेकिन रसोई की सफाई अपनी आंखों से नहीं देख पाते। हम सड़क किनारे पकवान खाते हैं, लेकिन उसमें इस्तेमाल तेल कितनी बार गर्म हुआ, यह नहीं जान पाते।

इसलिए खाद्य सुरक्षा व्यवस्था का मजबूत होना किसी सरकारी विभाग की औपचारिक जिम्मेदारी नहीं,बल्कि करोड़ों उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा है।

तुकाराम मुंढे की सख्ती ने कम से कम यह बहस जरूर छेड़ दी है कि खाने के अधिकार के साथ सुरक्षित भोजन का अधिकार भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

अब जरूरत है कि यह सख्ती कुछ महीनों की सुर्खी बनकर न रह जाए।

होटल साफ रहें...केवल निरीक्षण के दिन नहीं,हर दिन

स्कूल कैंटीन स्वस्थ भोजन दें...केवल आदेश के बाद नहीं,जिम्मेदारी से।

स्ट्रीट फूड सुरक्षित हो–केवल कार्रवाई के डर से नहीं,ग्राहक के स्वास्थ्य के सम्मान में।

और प्रशासन कार्रवाई करे–केवल किसी मुंढे जैसे सख्त अधिकारी के रहते नहीं,बल्कि एक मजबूत और जवाबदेह व्यवस्था के रूप में।

क्योंकि आखिरकार सवाल किसी होटल के लाइसेंस का नहीं है। सवाल हमारी थाली का है, हमारे बच्चों के स्वास्थ्य का है और उस भरोसे का है जिसके साथ हम रोज किसी दुकान, होटल या ठेले से खाना खरीदते हैं।

सख्ती स्वागतयोग्य है लेकिन सख्ती से पैदा हुआ डर नहीं,नियमों से पैदा हुई जिम्मेदारी ही स्थायी समाधान है।

इंटरनेट का विस्फोट?अब मासूम का कहां रहा बचपन,खंडित सामाजिक रिश्ते

इंटरनेट और सोशल मीडिया आधुनिक सभ्यता की ऐसी उपलब्धियाँ हैं, जिन्होंने मनुष्य के जीवन को अभूतपूर्व गति, सुविधा और संचार की शक्ति प्रदान की है।

संजीव कुमार ठाकुर
रायपुर,छत्तीसगढ़

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

ज्ञान, शिक्षा,सूचना, मनोरंजन और संवाद के असंख्य साधन आज हमारी उँगलियों पर उपलब्ध हैं। संसार की दूरियाँ सिमट गई हैं और दुनिया मानो एक छोटे-से गाँव में बदल गई है। लेकिन हर सुविधा का एक दूसरा पक्ष भी होता है। इंटरनेट और सोशल मीडिया का अनियंत्रित तथा असंतुलित उपयोग आज बच्चों के बचपन,पारिवारिक रिश्तों और सामाजिक संवेदनाओं के सामने गंभीर चुनौती बनकर खड़ा है।

आज तीन-चार वर्ष का मासूम बच्चा भी मोबाइल चलाना जानता है। माता-पिता अपनी व्यस्त दिनचर्या में बच्चे को शांत कराने के लिए मोबाइल उसके हाथ में थमा देते हैं। शुरुआत में यह सुविधा लगती है,लेकिन धीरे-धीरे मोबाइल बच्चे का सबसे प्रिय साथी बन जाता है। वह माता-पिता की गोद से अधिक मोबाइल की स्क्रीन में सुरक्षा और मनोरंजन तलाशने लगता है। बाहर खेलने,मिट्टी में उतरने,दोस्तों के साथ दौड़ने या प्रकृति को देखने की अपेक्षा उसे कार्टून,वीडियो और ऑनलाइन गेम अधिक आकर्षित करने लगते हैं। यहीं से बचपन के बदलने की कहानी शुरू होती है।

एक समय था जब बच्चों की पहचान उनकी खिलखिलाती हँसी,मिट्टी से सने कपड़ों, मैदानों की दौड़,पेड़ों पर चढ़ने की जिद और दोस्तों के साथ खेली जाने वाली गुल्ली-डंडा, कबड्डी,खो-खो,क्रिकेट,फुटबॉल और हॉकी से होती थी। शाम होते ही गलियाँ बच्चों की चहचहाहट से भर जाती थीं। घरों के आँगन में कैरम,लूडो और शतरंज की बिसात सजती थी। हारने वाला रूठता था और जीतने वाला मुस्कुराता था,लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों फिर दोस्त बन जाते थे।

आज अनेक शहरों और कस्बों की गलियाँ अपेक्षाकृत शांत हैं और बच्चों की दुनिया मोबाइल की छोटी-सी स्क्रीन में सिमटती जा रही है।

खेल के मैदान से स्क्रीन तक

खेल केवल शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम नहीं थे। वे जीवन जीने की पहली पाठशाला थे। कबड्डी बच्चों को साहस और सामूहिकता सिखाती थी,खो-खो सहयोग और अनुशासन सिखाता था,क्रिकेट धैर्य और रणनीति का अभ्यास कराता था। गुल्ली-डंडा और गिल्ली जैसे पारंपरिक खेल संसाधनों की कमी के बावजूद बच्चों को आनंद देना जानते थे।

आज ऑनलाइन गेमिंग ने इन खेलों की जगह काफी हद तक ले ली है। स्क्रीन पर जीतने की खुशी वास्तविक मैदान की खुशी जैसी नहीं होती। वास्तविक खेल में बच्चा धूप,हवा,मिट्टी, पसीने और मित्रता के बीच बड़ा होता है। वहाँ वह हारना सीखता है,फिर उठकर प्रयास करना सीखता है। डिजिटल खेलों में अक्सर प्रतिस्पर्धा अधिक तीव्र,आभासी और कई बार आक्रामक होती है।

बच्चों की शारीरिक गतिविधियाँ कम होने से मोटापा,शारीरिक निष्क्रियता,नींद की समस्याएँ, आँखों पर दबाव और गर्दन-पीठ से जुड़ी परेशानियों जैसी चिंताएँ बढ़ रही हैं। अत्यधिक स्क्रीन समय एकाग्रता और दिनचर्या को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए समस्या मोबाइल या इंटरनेट का अस्तित्व नहीं,बल्कि उसका अनियंत्रित उपयोग है।

मासूमियत पर आभासी दुनिया का प्रभाव

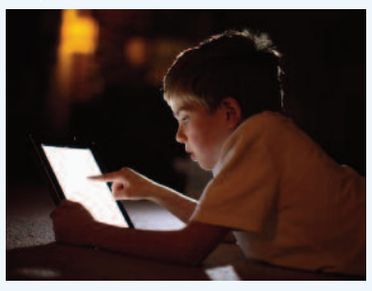

सोशल मीडिया ने बच्चों के सोचने और व्यवहार करने के तरीके को भी प्रभावित किया है। आभासी दुनिया में दिखाई देने वाली चमक-दमक, दिखावा,लोकप्रियता और त्वरित प्रसिद्धि बच्चों के मन में कम उम्र से ही तुलना और प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा कर सकती है।

अब बच्चा यह सोचने लगा है कि उसके कितने लाइक्स हैं,कितने फॉलोअर्स हैं और उसकी तस्वीर को कितने लोगों ने पसंद किया। बचपन की सहज मुस्कान कभी-कभी कैमरे के सामने बनाई गई कृत्रिम मुस्कान में बदलने लगती है। वह जीवन को जीने से अधिक उसे रिकॉर्ड करने लगता है।

भोजन सामने है,लेकिन पहले तस्वीर खींची जाती है। परिवार साथ बैठा है,लेकिन बातचीत के बजाय हर व्यक्ति अपनी-अपनी स्क्रीन पर है। घूमने गए हैं,लेकिन प्रकृति को देखने से अधिक उसे कैमरे में कैद करने की चिंता है। धीरे-धीरे अनुभव की जगह प्रदर्शन लेने लगता है।

एक छत के नीचे, फिर भी दूर

सोशल मीडिया का सबसे गंभीर प्रभाव केवल बच्चों पर नहीं,परिवार पर भी दिखाई देता है। एक ही घर में माता-पिता,बच्चे और बुजुर्ग रहते हैं, लेकिन मानसिक रूप से एक-दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। पहले भोजन का समय परिवार के संवाद का समय होता था। दिनभर की बातें होती थीं। दादा-दादी कहानियाँ सुनाते थे। बच्चे अपने विद्यालय और मित्रों की बातें बताते थे। माता-पिता बच्चों की भावनाओं को समझते थे।

आज भोजन की मेज पर भी मोबाइल उपस्थित है। कभी घर में घंटी बजने पर पूरा परिवार उत्सुकता से उठता था कि कौन आया है। अब संदेश की सूचना आते ही व्यक्ति सामने बैठे व्यक्ति को छोड़कर दूर बैठे किसी आभासी व्यक्ति से जुड़ जाता है।

रिश्ते समाप्त नहीं हुए हैं,लेकिन उनकी आत्मीयता का स्वरूप बदल रहा है। कभी चिट्ठी आने में कई दिन लगते थे,लेकिन उसमें भावनाएँ होती थीं। आज संदेश कुछ सेकंड में पहुँच जाता है,लेकिन कई बार उसमें वह आत्मीयता नहीं होती।

विशेषज्ञों की चेतावनी

मनोवैज्ञानिक जीन ट्वेंज ने अपनी पुस्तकों और शोध में स्मार्टफोन तथा सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग को किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक व्यवहार और अकेलेपन की प्रवृत्तियों से जोड़कर चर्चा की है। उनके काम ने इस बात पर व्यापक बहस को जन्म दिया है कि डिजिटल जीवन का अत्यधिक विस्तार बच्चों और किशोरों के मनोवैज्ञानिक विकास को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है।

सामाजिक मनोवैज्ञानिक जोनाथन हैट ने भी आधुनिक बचपन के स्क्रीन-केंद्रित होने और वास्तविक दुनिया के अनुभवों से दूर जाने को गंभीर सामाजिक-मानसिक चुनौती के रूप में रेखांकित किया है। उनका जोर इस बात पर है कि बच्चों को वास्तविक खेल,स्वतंत्र अनुभव और मानवीय संबंधों से जोड़ना आवश्यक है।

यूनेस्को की शिक्षा संबंधी रिपोर्टों में भी डिजिटल तकनीक को शिक्षा का उपयोगी साधन मानते हुए उसके संतुलित उपयोग की आवश्यकता पर बल दिया गया है। तकनीक तभी लाभकारी है,जब वह सीखने की प्रक्रिया को मजबूत करे,न कि बच्चे की पूरी दिनचर्या पर कब्जा कर ले।

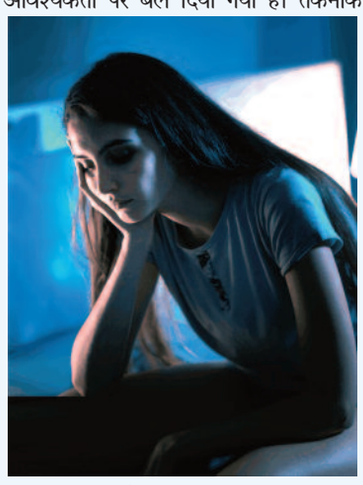

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी छोटे बच्चों के लिए स्क्रीन के उपयोग को सीमित रखने तथा पर्याप्त शारीरिक गतिविधि और नींद सुनिश्चित करने पर बल दिया है। इसका मूल संदेश यही है कि बच्चों के विकास में स्क्रीन के साथ-साथ वास्तविक दुनिया के अनुभव भी अनिवार्य हैं।

भारत के साइबर कानून विशेषज्ञ पवन दुग्गल लंबे समय से बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा, साइबर अपराध और डिजिटल जागरूकता के प्रश्नों पर ध्यान आकर्षित करते रहे हैं। इंटरनेट ज्ञान का विशाल भंडार है,लेकिन अभिभावकीय निगरानी और डिजिटल समझ के अभाव में वही माध्यम साइबर बुलिंग,अनुचित सामग्री और अन्य ऑनलाइन जोखिमों का कारण बन सकता है।

प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स के उदाहरण भी अक्सर दिए जाते हैं। दोनों ने अपने परिवारों में बच्चों के तकनीकी उपयोग के लिए सीमाएँ और संतुलन रखने की आवश्यकता पर सार्वजनिक रूप से चर्चा की थी। इससे एक महत्वपूर्ण संदेश मिलता है–तकनीक बनाने वाले लोग भी उसके विवेकपूर्ण उपयोग को आवश्यक मानते हैं।

केवल बच्चे ही क्यों?

यह समस्या केवल बच्चों तक सीमित नहीं है। युवा,माता-पिता और बुजुर्ग भी सोशल मीडिया के आकर्षण में बंधते जा रहे हैं। कई बार माता-पिता स्वयं मोबाइल से अलग नहीं हो पाते और फिर बच्चे से मोबाइल छोड़ने की अपेक्षा करते हैं।

बच्चे वही सीखते हैं जो वे देखते हैं

यदि माता-पिता घर लौटते ही मोबाइल में व्यस्त हो जाएँ,तो बच्चे को यह समझाना कठिन होगा कि मोबाइल से दूरी क्यों आवश्यक है। इसलिए डिजिटल अनुशासन की शुरुआत बच्चे से नहीं, परिवार से होनी चाहिए।

परिवार को प्रतिदिन कुछ समय ऐसा निर्धारित करना होगा जब मोबाइल,टेलीविजन और अन्य स्क्रीन बंद हों। उस समय परिवार केवल परिवार हो–बातचीत करे, हँसे, खेले और एक-दूसरे को सुने।

समाधान दूरी नहीं,संतुलन है...

इंटरनेट का विरोध समाधान नहीं है। आज शिक्षा,विज्ञान,चिकित्सा,रोजगार,बैंकिंग,संचार और ज्ञान के क्षेत्र में इंटरनेट अपरिहार्य है। समस्या तकनीक नहीं, उसका विवेकहीन उपयोग है।

बच्चों को इंटरनेट से दूर करने के बजाय उन्हें डिजिटल अनुशासन सिखाना होगा।उन्हें समझाना होगा कि इंटरनेट ज्ञान का माध्यम है, जीवन का विकल्प नहीं।

अभिभावकों को बच्चों के लिए आयु के अनुरूप सामग्री चुननी चाहिए। स्क्रीन टाइम की स्पष्ट सीमा होनी चाहिए। बच्चों को मोबाइल देकर चुप कराने की आदत से बचना होगा। उन्हें पुस्तकें पढ़ने,चित्रकला,संगीत,बागवानी,योग, तैराकी,साइकिल चलाने और खेलकूद के अवसर देने होंगे।

विद्यालयों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। शिक्षा केवल पाठ्यपुस्तकों और डिजिटल कक्षाओं तक सीमित नहीं हो सकती। खेल,संगीत, नाटक,साहित्य,प्रकृति-अध्ययन और सांस्कृतिक गतिविधियाँ बच्चे के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं।

सरकार और तकनीकी कंपनियों को भी बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण बनाने की दिशा में गंभीर प्रयास करने होंगे। आयु-उपयुक्त सामग्री,अभिभावकीय नियंत्रण, साइबर सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता को व्यापक स्तर पर बढ़ावा देना होगा।

लौटाना होगा बचपन

बचपन जीवन का सबसे सुंदर और सबसे संवेदनशील अध्याय है। उसे केवल तकनीकी दक्षता की प्रयोगशाला नहीं बनाया जा सकता। बच्चे को मोबाइल चलाना सिखाने से पहले उसे मनुष्य से प्रेम करना सिखाना आवश्यक है। उसे बताना होगा कि हारना बुरा नहीं है, किसी को हराकर खुश होना ही जीवन नहीं है। मित्रता केवल ऑनलाइन नहीं होती। किसी के कंधे पर हाथ रखना, दुख में साथ बैठना और बिना किसी कारण हँस देना भी जीवन की बड़ी उपलब्धियाँ हैं।

हमें बच्चों को फिर से मैदानों में भेजना होगा। उन्हें साइकिल चलाने देना होगा। उन्हें पेड़ की छाया में बैठना होगा। मिट्टी में खेलने देना होगा। किताब के पन्ने पलटने होंगे। दादा-दादी की कहानियाँ सुननी होंगी। परिवार के साथ भोजन करना होगा।

हमें यह तय करना होगा कि मोबाइल बच्चे के हाथ में एक साधन हो...उसका बचपन नहीं। इंटरनेट और सोशल मीडिया मानव सभ्यता की महान उपलब्धियाँ हैं। लेकिन तकनीक तभी वरदान है,जब मनुष्य उसका स्वामी बना रहे। यदि तकनीक हमारे समय,व्यवहार,संबंध और संवेदनाओं को नियंत्रित करने लगे,तो सुविधा धीरे-धीरे निर्भरता में बदल जाती है।

आज हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि बच्चे इंटरनेट चलाना सीखें या नहीं। प्रश्न यह है कि क्या वे इंटरनेट के साथ-साथ जीवन जीना भी सीख रहे हैं?

यदि आने वाली पीढ़ी तकनीकी रूप से दक्ष लेकिन भावनात्मक रूप से अकेली होगी, तो हमारी प्रगति अधूरी होगी। हमें ऐसी पीढ़ी चाहिए जो मोबाइल भी चला सके और मिट्टी में भी खेल सके;ऑनलाइन मित्र बना सके और पड़ोसी के घर भी जा सके,डिजिटल दुनिया को समझ सके और वास्तविक रिश्तों की गरमाहट को भी महसूस कर सके।

बच्चों के हाथों से मोबाइल छीनना समाधान नहीं है, लेकिन उनके हाथों से बचपन छिन जाने देना भी स्वीकार्य नहीं।आइए,तकनीक को जीवन का सहायक बनाएँ, जीवन का स्थानापन्न नहीं। बच्चों को इंटरनेट का ज्ञान दें,लेकिन उससे पहले उन्हें प्रकृति से प्रेम करना,परिवार के साथ बैठना, मित्र बनाना,हार-जीत को स्वीकारना और खुलकर हँसना सिखाएँ।

क्योंकि जिस दिन बच्चे फिर से मैदानों में लौटेंगे,गलियों में उनकी आवाज गूँजेगी, साइकिल की घंटी सुनाई देगी और आँगन में कैरम की बिसात सजेगी...उस दिन केवल बच्चों का बचपन ही नहीं लौटेगा,हमारे समाज की खोती हुई आत्मीयता भी लौटेगी।

महंगाई काबू में है,बस आम आदमी का बजट बेकाबू है

रसोई का गणित सरकार के अर्थशास्त्र से क्यों नहीं मिलता? महंगाई को समझना हो तो अर्थशास्त्र नहीं,किराने की दुकान जाइए...

रसोई का दरवाजा खुलते ही आज सबसे पहले बजट नजर आता है। चीनी महँगी है,तेल जेब का हिसाब बिगाड़ रहा है,दाल का हर निवाला सोचकर खाना पड़ रहा है और सब्जियों के बढ़ते दाम थाली का संतुलन बिगाड़ रहे हैं। दूध की मलाई अब सामान्य सुविधा नहीं रही। महंगाई ने सवाल बदल दिया है–पहले पूछा जाता था,आज क्या पकाएँ;अब सोचना पड़ता है,क्या छोड़ें। रोटी अब सिर्फ भोजन नहीं,मासिक बजट का हिस्सा बन गई है। जरूरी चीजें महँगी हों तो सबसे पहले बचत घटती है, फिर इच्छाएँ सीमित होती हैं। सहनशीलता को ताकत कहा जाता है, लेकिन लगातार बढ़ती कीमतों के बीच वही मजबूरी बन जाती है।

सरकारी दावों और बाजार की हकीकत के बीच दूरी साफ दिखती है। महंगाई नियंत्रण में होने की बात कही जाती है,लेकिन किराने की दुकान पर उसका असर नहीं दिखता। आँकड़े प्रतिशत में राहत दिखा सकते हैं,पर परिवार का बजट रुपये में चलता है। दाल महँगी हो तो वैश्विक कारण, तेल बढ़े तो अंतरराष्ट्रीय बाजार का हवाला मिलता है। सवाल है,सस्ताई के समय यही वैश्विक परिस्थितियाँ असरदार क्यों नहीं दिखतीं? आम आदमी बिना किसी आर्थिक डिग्री के महंगाई समझता है। चीनी,तेल,दूध और प्याज के भाव से वह महीने का अनुमान लगाता है। उसके लिए महंगाई कोई आर्थिक शब्द नहीं,रोज का अनुभव है। यही सरकारी भाषा और रसोई की भाषा के बीच बढ़ते भरोसे के अंतर की वजह है।

महंगाई ने ऐसा मध्यमवर्ग खड़ा कर दिया है जिसकी आय स्थिर है,लेकिन जरूरतों की कीमत लगातार बढ़ रही है। कागज पर वह गरीब नहीं, पर महीने के अंत में आय-व्यय का हिसाब उसे असुरक्षित कर देता है। घरों में अब बच्चों को उन दिनों की सस्ती चीजों के बारे में बताना पड़ता है, जो कभी सामान्य थीं। 'सस्ता' शब्द धीरे-धीरे अनुभव से निकलकर स्मृति बन रहा है। महंगाई का असर सिर्फ थाली पर नहीं,बचत,शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य की योजनाओं पर भी पड़ता है। आय का बड़ा हिस्सा जरूरी खर्च में जाए तो सपनों की जगह अपने आप छोटी हो जाती है। इस दबाव को केवल औसत आँकड़े पूरी तरह नहीं समझा सकते।

महंगाई ने परिवार की बातचीत और प्राथमिकताएँ बदल दी हैं। पहले घरेलू बजट एक व्यवस्था था,अब वह बदलती कीमतों से जूझता हिसाब बन गया है। पत्नी सब्जी,तेल और चीनी का अनुमान लगाती है,पति वेतन और बाकी खर्च का। समस्या एक ही है–जरूरतें अनेक,पैसा सीमित। कई परिवारों को भोजन की गुणवत्ता, बचत और छोटी इच्छाओं में से चुनाव करना पड़ता है। महंगाई सिर्फ चीजें महँगी नहीं करती, परिवार के फैसले भी बदलती है। आय का बड़ा हिस्सा जरूरी खर्च में जाए तो शिक्षा,स्वास्थ्य, यात्रा और आकस्मिक जरूरतों के लिए पैसा कम पड़ता है। यही रोजमर्रा का दबाव महंगाई को आर्थिक से बढ़ाकर सामाजिक समस्या बनाता है। बढ़ती कीमतों ने आर्थिक दूरी को समझने का तरीका बदल दिया है। अब केवल आय नहीं, यह भी देखना जरूरी है कि उस आय से परिवार कितनी जरूरतें पूरी कर पा रहा है। महंगाई का असर गरीब पर सबसे तीखा है, क्योंकि उसकी आय का बड़ा हिस्सा भोजन और जरूरी वस्तुओं पर खर्च होता है। मध्यमवर्ग भी इससे अछूता नहीं,क्योंकि उसकी बचत और भविष्य की योजनाएँ प्रभावित होती हैं। रिश्तेदारों और मित्रों की बातचीत में भी अब दाम जगह बना चुके हैं–तेल कहाँ सस्ता है,सब्जियाँ किस बाजार में कम हैं,दाल कितने की है। महंगाई ने सिर्फ बाजार नहीं,लोगों की प्राथमिकताएँ और बातचीत भी बदल दी हैं।

अर्थशास्त्र के सिद्धांत अपनी जगह हैं,लेकिन महंगाई की असली परीक्षा घर की थाली में होती है। मांग-आपूर्ति,वैश्विक बाजार और मुद्रास्फीति जैसे शब्द तभी मायने रखते हैं,जब उनका असर परिवार के खर्च में साफ दिखे। विशेषज्ञ इसे अस्थायी बताते हैं,लेकिन लंबे समय तक बनी ऊँची कीमतें आम आदमी के लिए अस्थायी नहीं रह जातीं। लगातार बढ़ती लागत से बचत घटती है, खर्च की प्राथमिकताएँ बदलती हैं और भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ती है। इसलिए महंगाई को केवल आर्थिक सूचकांक मानना अधूरा होगा। असली तस्वीर यह है कि एक सामान्य परिवार अपनी आय से कितना भोजन, ईंधन, शिक्षा और बचत सुरक्षित रख पा रहा है। यही महंगाई का वास्तविक असर है।

आम आदमी की परेशानी समझने का सबसे सीधा रास्ता उसकी रसोई से होकर जाता है। बड़ी घोषणाओं की सफलता तभी मानी जाएगी,जब रोजमर्रा की जरूरी चीजें उसकी पहुँच में रहें। नियंत्रण की बातें तभी भरोसा जगाएँगी,जब उनका असर बाजार में दिखे। गरीब और मध्यमवर्गीय परिवार के लिए चीनी,तेल, दाल,दूध और सब्जियाँ मामूली वस्तुएँ नहीं, बुनियादी जरूरतें हैं। इनके दाम बढ़ते हैं तो सबसे पहले भोजन,फिर बचत और अंततः भविष्य प्रभावित होता है। आम आदमी को भाषण नहीं, राहत चाहिए। उसकी आवाज आँकड़ों में नहीं, थाली में सुननी होगी। जब तक जरूरी चीजें उसकी पहुँच में नहीं आतीं, महंगाई पर नियंत्रण का दावा अधूरा रहेगा।

प्रो. आरके जैन अरिजीत
बड़वानी,मध्यप्रदेश

कवितायें

मेरा कोई नाम नहीं

प्रोफेसर शाम लाल कौशल
रोहतक
हरियाणा

दुनिया में मैंने कभी भी
किया कोई ऐसा काम नहीं!
इसलिए तो मेरे प्यारे दोस्तों
अपनों में भी मेरा कोई नाम नहीं!
यह दुनिया है सारी मतलब की
इस सच्चाई से मैं अनजान नहीं!
बेशक ले रहे हैं बहुत दौलत लोग
दिल से लेकिन कोई धनवान नहीं।
वेशभूषा बेशक पाएं अवतार जैसी
लेकिन असल में तो भगवान नहीं!
आदमी तो घूम रहे हैं बहुत यहां
असल में इनमें से सभी इंसान नहीं।
रब ने यूं तो दे रखा है बहुत कुछ हमें
परंतु करते कभी हम गुणगान नहीं।
ऊंची ऊंची कोठियां बना रखी है लोगों ने
लेकिन कौन है जो यहां मेहमान नहीं।
लाखों आए और लाखों चले गए यहां से
मिलती किसी की भी यहां पहचान नहीं।
ऊंचे ऊंचे पद प्राप्त कर लेते हैं लोग यहां
लेकिन बन पाता कोई भी आसमां नहीं।
जिसे भी देखो उलझा हुआ है उधेड़बुन में
किसी के चेहरे पर मिलती मुस्कान नहीं।

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

सम्पादक

महिला पुलिसकर्मियों के लिए पहली बार ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग,सीआरपी का भी प्रशिक्षण

पुलिस लाइन में स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम,विशेषज्ञ चिकित्सकों ने प्रारंभिक पहचान और नियमित जांच के महत्व की दी जानकारी

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,23 अगस्त 2026
(घटती-घटना)।

महिला पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्वास्थ्य को लेकर सरगुजा पुलिस के मार्गदर्शन में रविवार को पुलिस लाइन,अंबिकापुर में विशेष ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग एवं सीआरपी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। सरगुजा संभाग में पहली बार महिला पुलिसकर्मियों के लिए विशेष रूप से आयोजित इस पहल में स्वास्थ्य जांच के साथ महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर की शुरुआती पहचान और समय पर उपचार के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम का आयोजन भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी,जिला शाखा सरगुजा,इंडियन मेडिकल एसोसिएशन,सरगुजा और लायंस क्लब अंबिकापुर के संयुक्त तत्वावधान में किया गया।

नियमित जांच से समय पर हो सकती है बीमारी की पहचान : कार्यक्रम में कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉ. पीयू प्रकाश सक्सेना ने ब्रेस्ट कैंसर से संबंधित चिकित्सकीय जानकारी दी। उन्होंने महिलाओं को बीमारी के शुरुआती लक्षणों, समय पर स्क्रीनिंग और नियमित स्वास्थ्य जांच के महत्व के बारे में बताया। इस दौरान उपस्थित महिला पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की स्क्रीनिंग कर आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श भी दिया गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सरगुजा के सचिव डॉ. अर्पण सिंह चौहान ने कहा कि महिला पुलिस अधिकारी और कर्मचारी अपने शासकीय दायित्वों के साथ परिवार एवं समाज के प्रति भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाती हैं।

ऐसे में उनके स्वास्थ्य की नियमित जांच और समय पर चिकित्सकीय परामर्श बेहद जरूरी है। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग करने के साथ समय पर स्क्रीनिंग के लिए प्रेरित करना है।

आम महिलाओं के लिए भी रही स्क्रीनिंग की सुविधा : कार्यक्रम की खास बात यह रही कि सरगुजा की आम जनता, विशेषकर इच्छुक महिलाओं के लिए भी ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग और चिकित्सकीय परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई गई। इस पहल के जरिए पुलिस विभाग की महिला कर्मियों के साथ आम नागरिकों को भी समय पर स्वास्थ्य जांच के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया। कार्यक्रम पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज दीपक झा एवं डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा राजेश अग्रवाल के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रितेश चौधरी,रक्षित निरीक्षक अंबिकापुर तृप्ति सिंह राजपूत,सूबेदार गुलशन चंद्रा,सूबेदार पेमिन वर्मा सहित सरगुजा रेंज के विभिन्न जिलों से महिला पुलिस अधिकारी-कर्मचारी तथा पुलिस चिकित्सालय के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में पुलिस विभाग,चिकित्सा विशेषज्ञों और सामाजिक संस्थाओं की संयुक्त सहभागिता से महिलाओं के स्वास्थ्य,समय पर बीमारी की पहचान और स्वास्थ्य जागरूकता का संदेश दिया गया।

डॉक्टरों की टीम ने दी स्वास्थ्य सेवाएं

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सरगुजा की ओर से डॉ. सुजीत,डॉ. हरप्रीत,डॉ. सुधांशु,डॉ. सुषमा, डॉ. रितेश,डॉ. स्वप्निल और डॉ. अखिलेश ने चिकित्सकीय टीम के रूप में सहभागिता की और स्क्रीनिंग एवं स्वास्थ्य सेवाओं में सहयोग किया।

सीआरपी प्रशिक्षण में सिखाई जीवन बचाने की तकनीक

कार्यक्रम के दूसरे चरण में डॉ. श्रीकांत सिंह ने सीआरपी प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण के दौरान आपातकालीन परिस्थितियों में प्राथमिक जीवनरक्षक सहायता देने की आवश्यक तकनीकों की जानकारी दी गई और प्रतिभागियों को इसका व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया।

मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को डंडे से पीटा,गंभीर चोट के बाद बेहोश

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,23 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

स्कूल रोड स्थित महिला मंडल कॉम्प्लेक्स में दुकान के पास बैठे मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति से मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि स्टेशनरी दुकानदार ने उसे गाली-गलौज करते हुए डंडे से पीटा। मारपीट में उसके सिर,हाथ-पैर में गंभीर चोटें आईं और वह मौके पर बेहोश हो गया। सूचना पर पुलिस पहुंची और घायल को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। जानकरी के अनुसार स्कूल रोड निवासी अनिल सोनी महिला मंडल कॉम्प्लेक्स में ज्वेलरी व स्टेशनरी की दुकान संचालिता है। उसने अनुसार रिपोर्ट दर्ज कराया है कि दो साल से एक मानसिक रूप से अस्वस्थ करीब 40 वर्षीय व्यक्ति उनकी दुकान के आसपास आता-जाता था और वहीं बैठता था। अनिल सोनी उसे खाने के लिए कुछ देते थे, जिसके बाद वह वहां से चला जाता था। 21 अगस्त की सुबह करीब 10.15 बजे उक्त व्यक्ति दुकान के पास बैठा था। इसी दौरान बगल में स्टेशनरी की दुकान संचालित करने वाला सादाब सिद्दीकी उर्फ बाबू ने उसे वहां बैठने को लेकर गाली-गलौज शुरू कर दी और लकड़ी के डंडे से व्यक्ति की पिटाई कर दी। मारपीट देखकर सड़क से गुजर रहे लोगों ने बीच-बचाव किया। घायल व्यक्ति के सिर और हाथ-पैर में गंभीर चोटें आईं और वह बेहोशी हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची,लेकिन तब तक आरोपी वहां से फरार हो गया था। घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया।

विवाद पर शराब की बोतल से सिर पर हमला

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,23 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

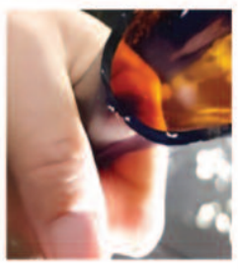

बगीचा चौक के पास बाइक रोकते समय पैर टकराने की बात को लेकर युवक से गाली-गलौज और मारपीट का मामला सामने आया है। विवाद के दौरान युवक ने हाथ-मुक्के से मारपीट करने के बाद जान से मारने की नियत से पास पड़ी कांच की शराब की खाली बोतल से सिर पर हमला कर दिया। घायल का बतौली शांतिपारा अस्पताल में उपचार कराया गया। जानकारी के अनुसार ग्राम महेशपुर बटईकेला निवासी अमित प्रजापति 20 अगस्त को अपने दोस्त रामकृपाल प्रजापति के साथ राशन कार्ड में त्रुटि सुधार कराने बाइक से जनपद कार्यालय बतौली गया था। अधिक बारिश होने के कारण दोनों वहीं रुक गए। बारिश थमने के बाद रात करीब 8 बजे दोनों वापस लौट रहे थे। अमित के अनुसार बगीचा चौक के पास बाइक रोकते समय उसका पैर वहां खड़े रितिक शर्मा उर्फ लल्ला निवासी बतौली से हल्का टकरा गया। इसी बात को लेकर रितिक ने गाली-गलौज शुरू कर दी और हाथ-मुक्के से मारपीट करने लगा। अमित ने गाली देने से मना किया तो रिकित ने पास पड़ी कांच की खाली शराब की बोतल उठाकर उसके सिर पर दे मारी। सिर में चोट लगने से अमित के काफी खून निकलने लगा और वह जमीन पर गिर गया। इसके बाद उसे पुनः शराब की बोतल से मारने की कोशिश की। इसी दौरान अमित के दोस्त रामकृपाल और मौके पर मौजूद राहगीरों ने बीच-बचाव कर उसे बचाया। घटना के बाद रामकृपाल घायल अमित को बतौली शांतिपारा अस्पताल लेकर गया,जहां उसका उपचार कराया गया। अमित की रिपोर्ट पर बतौली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

महिला स्वास्थ्य कर्मचारी के घर का दरवाजा तोड़कर जेवर व नकदी चोरी

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,23 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

लुण्ड्रा थाना क्षेत्र के ग्राम पटोरा में अज्ञात चोर ने किराये के मकान का पिछला दरवाजा तोड़कर अलमारी में रखे नकदी और चांदी के जेवरात पार कर दिए। चोरी गए सामान की कुल कीमत करीब 34,500 रुपए बताई गई है। पीड़िता ने लुण्ड्रा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस के अनुसार ग्राम पटोरा निवासी रेखा कुर्रे किराये के मकान में परिवार के साथ रहती है और धौरपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नौकरी करती है। 21 अगस्त को वह रोज की तरह सुबह करीब 10 बजे ड्यूटी के लिए धौरपुर गई थीं। इसी दौरान करीब ढाई बजे उनके परिचित ने फोन कर घर में चोरी होने की जानकारी दी। सूचना मिलने पर रेखा घर पहुंचीं तो किराये के कमरे के पीछे का दरवाजा टूटा हुआ था। चोर दरवाजे को लात मारकर अंदर घुसे थे। इसके बाद अलमारी का लॉकर तोड़कर उसमें रखे 10,500 रुपए नकद और चांदी की दो जोड़ी पायल, बिछिया व चैन चोरी कर ले गए। नकदी समेत कुल नुकसान 34,500 रुपए का बताया गया है।

घर का दरवाजा बाहर से बंदकर दुकान में चोरी

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,23 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम भवराडांड नंदिटिकरा में अज्ञात चोर ने किराना दुकान का ताला तोड़कर करीब 19 हजार रुपए का सामान और नकदी पार कर दी। वारदात के दौरान चोरों ने दुकान संचालक और उसके पड़ोसी के घर के दरवाजे बाहर से कपड़े से बांध दिए थे। पुलिस के अनुसार सत्यनारायण कुशवाहा भवराडांड मान नदी पुल के पास किराना दुकान के साथ एसबीआई का ग्राहक सेवा केंद्र भी संचालित करता है। 10 अगस्त की शाम करीब 7 बजे वह दुकान बंद कर अपने कमरे में चला गया। खाना खाने के बाद वह सो गया। रात करीब 3 बजे उसके पड़ोसी सुदामा कुशवाहा की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके घर का दरवाजा बाहर से कपड़े से बांधा गया था। किसी तरह दरवाजा खोलकर बाहर निकला तो सत्यनारायण की दुकान का ताला टूटा हुआ दिखाई दिया।

मानसून ने अंबिकापुर को भिगोया,जिले में 42 फीसदी पीछे

22 अगस्त तक 1014.1 मिमी बारिश,औसत का 83.1 फीसदी,संभाग में सरगुजा 42 फीसदी पीछे तो बलरामपुर 43 फीसदी आगे

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,23 अगस्त 2026
(घटती-घटना)।

मानसून इस बार अंबिकापुर पर मेहरबान है। जून में कमजोर शुरुआत के बाद जुलाई और अगस्त में हुई झमाझम बारिश से शहर में मानसूनी बारिश का आंकड़ा 1000 मिमी के पार पहुंच गया है। शनिवार को मौसम कार्यालय में दिनभर में 46.2 मिमी बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही 22 अगस्त की शाम तक अंबिकापुर में कुल मानसूनी बारिश 1014.1 मिमी हो गई है। यह मानसून की औसत वर्षा 1220 मिमी का 83.1 प्रतिशत है। मौसम वैज्ञानिक एएम भट्ट के अनुसार अंबिकापुर ने इस वर्ष औसत मानसूनी वर्षा के लक्ष्य को सामान्य समय से करीब 38 दिन पहले हासिल कर लिया है। सामान्य वर्षा औसत से प्लस-माइनस 19 प्रतिशत तक मानी जाती है। अभी मानसून का एक महीने से अधिक समय शेष है। ऐसे में बारिश का आंकड़ा औसत के और करीब पहुंचने की संभावना है। अंबिकापुर में बारिश की स्थिति अच्छी है,लेकिन पूरे सरगुजा संभाग में बारिश का वितरण असमान है। अंबिकापुर में जून में मानसून की शुरुआत कमजोर रही। पूरे महीने 109.3 मिमी बारिश हुई। जुलाई में मानसून सक्रिय हुआ और महीनेभर में 462 मिमी बारिश दर्ज की गई। अगस्त में भी बारिश का दौर जारी है। 22 अगस्त की शाम तक अगस्त में 442.8 मिमी बारिश हो चुकी है। इस तरह जून,जुलाई और अगस्त में अब तक कुल 1014.1 मिमी बारिश दर्ज की जा चुकी है।

अगस्त में 500 मिमी तक पहुंचने का अनुमान : मौसम वैज्ञानिक एएम भट्ट के अनुसार मानसून अभी सक्रिय रहने की उम्मीद है। अगस्त में अब तक 442.8 मिमी बारिश हो चुकी है और महीने का करीब एक सप्ताह अभी बाकी है। ऐसे में अगस्त की कुल बारिश 500 मिमी के आसपास पहुंच सकती है। अंबिकापुर की मानसूनकालीन औसत वर्षा 1220 मिमी है। वर्तमान आंकड़ा औसत से 205.9 मिमी कम है। मानसून के शेष समय में अच्छी बारिश हुई तो औसत वर्षा का आंकड़ा पार हो सकता है।

संभाग में बारिश का असमान वितरण, सरगुजा 42 फीसदी पीछे : मौसम केंद्र रायपुर के 1 जून से 23 अगस्त 2026 तक के जिला-वार आंकड़ों के अनुसार सरगुजा संभाग में कुल 795 मिमी बारिश दर्ज की गई है। सामान्य वर्षा 857.1 मिमी के मुकाबले यह 7 फीसदी कम है, फिर भी संभाग की स्थिति सामान्य श्रेणी में है। संभाग में सबसे कम बारिश सरगुजा जिले में हुई है। यहां 514.1 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि सामान्य वर्षा 883.7 मिमी है। इस तरह जिले में 42 फीसदी कम बारिश हुई है और सरगुजा अल्प वर्षा की श्रेणी में है। इसके विपरीत बलरामपुर में 1027.6 मिमी बारिश दर्ज हुई है,जबकि सामान्य वर्षा 716.5 मिमी है। यहां सामान्य से 43 फीसदी अधिक बारिश हुई है और जिला अधिक वर्षा की श्रेणी में है।

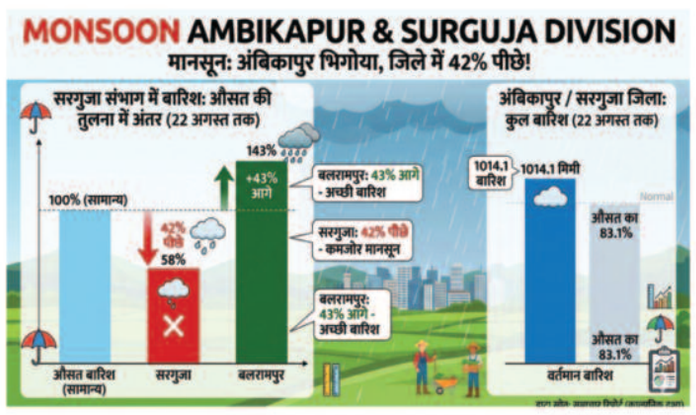

सूरजपुर में सामान्य, जशपुर में 35 फीसदी कमी : सूरजपुर में 879.9 मिमी बारिश हुई है,जबकि सामान्य वर्षा 892.1 मिमी है। यहां केवल 1 फीसदी कमी है और स्थिति सामान्य है। जशपुर में 659.8 मिमी बारिश दर्ज हुई है। सामान्य वर्षा 1009.1 मिमी के मुकाबले यहां 35 फीसदी कमी है।

जशपुर अल्प वर्षा की श्रेणी में है। कोरिया में 685.9 मिमी बारिश हुई है, जो सामान्य 835.7 मिमी से 18 फीसदी कम है। इसके बावजूद जिला सामान्य श्रेणी में है। वहीं मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) में 857.6 मिमी बारिश हुई है,जो सामान्य 835.6 मिमी से 3 फीसदी अधिक है।

मृतक को पिता बताकर जमीन हड़पने का आरोप,फर्जी दस्तावेजों से नामांतरण का सनसनीखेज मामला

फर्जी आधार और मृत्यु प्रमाण-पत्र के सहारे राजस्व रिकॉर्ड में नाम चढ़ाने का आरोप,पटवारी से मिलीभगत का दावा,ग्रामीणों ने एसडीएम से की शिकायत

-सुदामा राजवाड़े-
कुसमी,23 अगस्त 2026
(घटती-घटना)।

अनुविभाग कुसमी के ग्राम जिगनियां में जमीन के राजस्व रिकॉर्ड में कथित फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि एक व्यक्ति ने मृतक को अपना पिता बताकर कथित तौर पर फर्जी आधार कार्ड और मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार कराया और इसके आधार पर कीमती जमीन अपने नाम दर्ज करा ली। मामले में हल्का पटवारी से कथित मिलीभगत का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुसमी से शिकायत कर निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है।

2012 में हुई मौत,2025 तक रिकॉर्ड में नाम : शिकायत के अनुसार ग्राम जिगनियां के पारा अम्बाकोना निवासी लोया,पिता चकिया का निधन वर्ष 2012 में हो चुका था। इसके बावजूद उनका नाम वर्ष 2025 तक राजस्व अभिलेखों में दर्ज बताया जा रहा है। आरोप है कि इसी बीच ग्राम जलबोथा निवासी गोवर्धन,पिता लेडंग ने खुद को लोया का पुत्र बताते हुए कथित रूप से जमीन पर अपना दावा पेश किया। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि गोवर्धन ने कथित तौर पर जलबोथा से लोया के नाम का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया और स्वयं को लोया का पुत्र दर्शाते हुए फर्जी आधार कार्ड भी तैयार कराया।

पटवारी से सांठगांठ का आरोप : ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि गोवर्धन ने हल्का पटवारी से कथित सांठगांठ कर अन्य हिस्सेदारों अथवा खातेदारों को सूचना दिए बिना राजस्व अभिलेखों में अपना नाम दर्ज करा लिया। शिकायतकर्ताओं ने इस नामांतरण की प्रक्रिया, प्रस्तुत दस्तावेजों और संबंधित राजस्व रिकॉर्ड की जांच कराने की मांग की है।

मृतक का कोई पुत्र नहीं होने का दावा : शिकायत में एक महत्वपूर्ण दावा यह भी किया गया है कि मृतक लोया का कोई पुत्र नहीं था,बल्कि उनकी केवल एक पुत्री है, जिसका विवाह गोपातु गांव में हुआ है और वह वर्तमान में जीवित है। ऐसे में गोवर्धन के स्वयं को मृतक का पुत्र बताने के दावे पर सवाल उठाए गए हैं।

2003 की मतदाता सूची से भी उठे सवाल : ग्रामीणों के मुताबिक वर्ष 2003 की मतदाता सूची में गोवर्धन का परिवार ग्राम पंचायत जलबोथा का निवासी दर्ज है। इसमें उसके पिता लेडंग,पत्नी और भाई का उल्लेख होने का दावा किया गया है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि यह रिकॉर्ड गोवर्धन के जिगनियां निवासी लोया का पुत्र होने के दावे की जांच में महत्वपूर्ण हो सकता है।

क्या जमीन के पीछे सक्रिय हैं भू-माफिया? मामले को लेकर ग्रामीणों ने पूरे घटनाक्रम के पीछे भू-माफियाओं की संभावित भूमिका की भी आशंका जताई है। हालांकि इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से दस्तावेजों की सत्यता, नामांतरण प्रक्रिया और संबंधित लोगों की भूमिका की गहन जांच कराने की मांग की है।

एसडीएम से निष्पक्ष जांच और नाम हटाने की मांग : ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय में आवेदन देकर मामले की निष्पक्ष जांच, कथित फर्जी दस्तावेज तैयार करने और राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया की जांच तथा दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

यूपी-झारखंड की शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार,भेजा जेल

आबकारी-पुलिस की संयुक्त कार्रवाई,15.75 बल्क लीटर विदेशी मदिरा जब्त

-संवाददाता-
बलरामपुर,23 अगस्त 2026
(घटती-घटना)।

जिले में अवैध शराब के परिवहन, भंडारण और बिक्री के खिलाफ जिला प्रशासन का अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में आबकारी एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश और झारखंड की शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से कुल 15.75 बल्क लीटर विदेशी मदिरा बरामद की गई है।

सीमावर्ती क्षेत्र में घेराबंदी कर पकड़ा : कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी के निर्देश पर आबकारी एवं पुलिस विभाग की टीम द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार निगरानी और जांच की जा रही है। इसी दौरान वृत्त वाड्रफनगर क्षेत्र में संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर ग्राम सिलाजु, थाना रामचंद्रपुर निवासी अर्जुन साव को पकड़ा। जांच के दौरान उसके कब्जे से दूसरे राज्यों की विदेशी मदिरा बरामद हुई।

ये शराब हुई जब्त

- 8 पीएम व्हिस्की: 20 नग, प्रत्येक 375 एमएल
- रॉयल स्टैग: 6 नग, प्रत्येक 375 एमएल
- किंगफिशर बीयर कैन: 12 नग, प्रत्येक 500 एमएल
- कुल मात्रा: 15.75 बल्क लीटर विदेशी मदिरा

आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई : मामले में आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क), 34(2), 36 एवं 59(क) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया,जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

सीमावर्ती इलाकों पर विशेष नजर : जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि दूसरे राज्यों से होने वाले अवैध शराब के परिवहन और बिक्री को रोकने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी और कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। प्रशासन ने अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

जश्ने ईद मिलादुन्नबी 26 अगस्त को..अमन-भाईचारे का संदेश देगा अंबिकापुर

सीरतुन्नबी कमेटी की तैयारियां तेज,मेधावी विद्यार्थियों,खिलाड़ियों,समाजसेवियों,चिकित्सकों व अधिवक्ताओं का होगा सम्मान

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,23 अगस्त 2026
(घटती-घटना)।

पैगंबर मोहम्मद साहब (स.अ.व.) के जन्मदिन के अवसर पर जश्ने ईद मिलादुन्नबी का पर्व इस वर्ष 26 अगस्त को परंपरागत और गरिमामय तरीके से मनाया जाएगा। सीरतुन्नबी कमेटी अंबिकापुर के तत्वावधान में आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर शहर में तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। आयोजन के माध्यम से अमन, शांति,बंधुत्व, महिला अधिकार, सांप्रदायिक सद्भाव और आपसी भाईचारे का संदेश दिया जाएगा।

मेधावी विद्यार्थियों से लेकर खिलाड़ियों तक का सम्मान : हर वर्ष की तरह इस बार भी शिक्षा, खेल और समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। सरगुजा जिले में 10 वीं और 12 वीं की परीक्षा में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अलावा UPSC और CGPSC में सफलता हासिल करने वाले जिले के होनहार युवाओं को भी सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर खेल के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ियों के साथ समाजसेवा के माध्यम से जरूरतमंदों की मदद करने वाले समाजसेवियों और सामाजिक संस्थाओं को भी सम्मानित किया जाएगा। मदरसा के बच्चों,प्रतिभावान युवा अधिवक्ताओं और चिकित्सकों का सम्मान भी कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण रहेगा।

प्रबुद्ध हस्ती को मिलेगा लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड : सरगुजा जिले में समाज के लिए अभूतपूर्व योगदान देने वाली किसी प्रबुद्ध हस्ती को 'लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड' से सम्मानित किया जाएगा। वहीं पिछले वर्ष के आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पूर्व अध्यक्ष जमाल खान मोनू, कार्यकारी अध्यक्ष मजुल खान और सद्दाम खान को भी सम्मानित किया जाएगा।

सभी धर्मगुरु देंगे भाईचारे का संदेश

आयोजन में सांप्रदायिक सद्भावना की मिसाल पेश करते हुए समाज के विभिन्न धर्मगुरुओं को भी आमंत्रित किया गया है। धर्मगुरु पैगंबर मोहम्मद साहब (स.अ.व.) की जीवनी और उनके अमन,शांति,इंसानियत तथा भाईचारे के संदेश पर प्रकाश डालेंगे।

शहर के मोहल्लों से निकलेगा जुलूस,कला केंद्र मैदान में मुख्य आयोजन

ईद मिलादुन्नबी का जुलूस शहर के विभिन्न मोहल्लों से होता हुआ कला केंद्र मैदान पहुंचेगा,जहां मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आयोजन को लेकर शहर को आकर्षक ढंग से सजाने-संवारने की तैयारियां भी चल रही हैं। अपने-अपने मोहल्ले की सर्वश्रेष्ठ सजावट करने वाले कार्यकर्ताओं को भी पुरस्कृत किया जाएगा।

नई कमेटी के नेतृत्व में आयोजन की तैयारी

अंबिकापुर शहर की 13 एदारा कमेटियों के सदस्यों और मुस्लिम समाज के प्रमुखजनों की स्थानीय जाकिर हुसैन हॉल में हुई बैठक में सीरतुन्नबी कमेटी के नए पदाधिकारियों का चयन किया गया। नव नियुक्त अध्यक्ष मेराज गुड्डू और कार्यकारी अध्यक्ष मोहम्मद नियाजुद्दीन खान निक्की के नेतृत्व में समाज के लोग आयोजन को सफल बनाने में जुटे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अध्यक्ष मेराज गुड्डू,कार्यकारी अध्यक्ष नियाजुद्दीन खान निक्की,सचिव फैजान अहमद,अशफाक अली,बाबर इदरीशी, शादाब रिजवी,जमाल खान मोनू,मोइनुद्दीन अंसारी सहित अन्य पदाधिकारी एवं समाज के प्रमुखजन उपस्थित रहे।

बैकुंठपुर पालिका अध्यक्ष की दौड़ में कमलेश शर्मा का नाम तेज

अनारक्षित सीट से बढ़ाई सियासी हलचल, दोनों दलों में नाम को लेकर उत्साह

- वरिष्ठ पत्रकार एवं प्रेस क्लब कोरिया के अध्यक्ष
- पीजी कॉलेज छात्रसंघ अध्यक्ष भी रह चुके हैं
- भाजपा एनजीओ प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्यसन्मिति सदस्य
- सामाजिक, विधिक सेवा और रेडक्रॉस जैसी संस्थाओं से भी जुड़ाव

छात्र राजनीति से पत्रकारिता और सामाजिक सेवा तक का अनुभव दे सकता है नई दिशा!

पालिका अध्यक्ष की कुर्सी अनारक्षित क्या हुई...दावेदारों की कतार में कमलेश शर्मा का नाम भी चमका!

पत्रकारिता से संगठन की राजनीति तक पहुंचे कमलेश शर्मा,अब बैकुण्ठपुर पालिका अध्यक्ष की रेस में नाम क्यों?

अध्यक्ष पद की रेस में कमलेश शर्मा की चर्चा तेज, पत्रकारिता से राजनीति तक के सफर पर टिकी नजर

पत्रकारिता,छात्र राजनीति और सामाजिक सक्रियता के बाद अब पालिका अध्यक्ष की दावेदारी? कमलेश शर्मा पर नजर

बैकुण्ठपुर पालिका अध्यक्ष कौन? कमलेश शर्मा के नाम की चर्चा ने सियासी समीकरणों को दी नई हवा

छात्रसंघ अध्यक्ष से प्रदेश कार्यसमिति तक,अब नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी पर कमलेश शर्मा की नजर?

कमलेश शर्मा की संभावित दावेदारी से बैकुण्ठपुर की राजनीति गरम,दोनों दलों में चर्चाओं का दौर

अनारक्षित मुक्त सीट ने खोला रास्ता, बैकुण्ठपुर में कमलेश शर्मा का नाम बना सियासी चर्चा का केंद्र

दावेदारी की चर्चा से बढ़ी हलचल : क्या बैकुण्ठपुर को कमलेश शर्मा के रूप में मिलेगा नया राजनीतिक चेहरा?

-रवि सिंह-

बैकुण्ठपुर,23 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

बैकुण्ठपुर नगर पालिका के आगामी चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां अब धीरे-धीरे तेज होने लगी हैं,अध्यक्ष पद के लिए इस बार अनारक्षित मुक्त सीट होने के बाद राजनीतिक दलों के भीतर संभावित चेहरों को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। दिसंबर में चुनाव होने की संभावित चर्चा के बीच जहां कई पुराने और नए चेहरे अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं, वहीं बैकुण्ठपुर के वरिष्ठ पत्रकार एवं प्रेस क्लब कोरिया के अध्यक्ष कमलेश शर्मा का नाम भी अध्यक्ष पद के संभावित दावेदार के रूप में तेजी से चर्चा में आने लगा है।

हालांकि अभी तक किसी भी राजनीतिक दल की ओर से कमलेश शर्मा को अध्यक्ष पद का अधिकृत प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है और न ही उनकी ओर से औपचारिक रूप से चुनाव लड़ने की घोषणा सामने आई है, इसके बावजूद राजनीतिक,सामाजिक और संगठनात्मक हलकों में उनके नाम को लेकर चर्चा लगातार बढ़ रही है, कमलेश शर्मा की संभावित दावेदारी को इसलिए भी अलग नजर से देखा जा रहा है क्योंकि उनका सार्वजनिक जीवन केवल एक राजनीतिक संगठन तक सीमित नहीं रहा है, छात्र राजनीति से शुरुआत, लंबे समय से पत्रकारिता में सक्रियता, सामाजिक संस्थाओं से जुड़ाव,विधिक सेवा के क्षेत्र में जिम्मेदारी और अब भाजपा एनजीओ प्रकोष्ठ में प्रदेश कार्यसमिति सदस्य के रूप में संगठनात्मक भूमिका–इन तमाम पहलुओं को उनके समर्थक अध्यक्ष पद की संभावित दावेदारी की ताकत के रूप में देख रहे हैं।

अनारक्षित सीट ने बढ़ाया मुकाबले का दायरा

नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए सीट अनारक्षित मुक्त होने के बाद अब चुनावी मैदान में संभावित दावेदारों की संख्या बढ़ने की संभावना है, आरक्षण की स्थिति किसी विशेष वर्ग तक सीमित नहीं होने से राजनीतिक दलों के पास कई विकल्प खुले हैं,स्थानीय निकाय चुनाव में केवल पार्टी संगठन की पकड़ ही निर्णायक नहीं होती,वार्ड स्तर का जनसंपर्क,सामाजिक समीकरण,व्यक्तिगत पहचान,विभिन्न वर्गों के बीच स्वीकार्यता और स्थानीय मुद्दों की समझ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है,यही कारण है कि राजनीतिक दल चुनाव से काफी पहले संभावित चेहरों को लेकर आंतरिक स्तर पर चर्चा शुरू कर देते हैं,बैकुण्ठपुर में भी इसी तरह का माहौल बनता दिखाई दे रहा है,इस राजनीतिक चर्चा में कमलेश शर्मा का नाम सामने आना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वे लंबे समय से शहर की गतिविधियों और स्थानीय मुद्दों के बीच सक्रिय रहे हैं।

पत्रकारिता से बना शहर के मुद्दों से सीधा जुड़ाव

कमलेश शर्मा की सार्वजनिक पहचान का सबसे बड़ा हिस्सा उनकी पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है, लंबे समय तक पत्रकारिता में सक्रिय रहने के कारण उन्होंने बैकुण्ठपुर सहित कोरिया जिले के सामाजिक,प्रशासनिक और जनहित से जुड़े मुद्दों को करीब से देखा है,पत्रकारिता के दौरान शहर की समस्याओं को उठाने और विभिन्न वर्गों के लोगों से संपर्क रखने के कारण उनका जनसंपर्क लगातार बना रहा,यही जनसंपर्क अब उनके संभावित राजनीतिक सफर को लेकर चर्चा का आधार बन रहा है,राजनीति और पत्रकारिता की भूमिकाएं भले अलग हों,लेकिन स्थानीय स्तर पर लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन में रहने से व्यक्ति को शहर की समस्याओं,प्रशासनिक व्यवस्था और जनता की अपेक्षाओं की समझ विकसित होती है,कमलेश शर्मा के समर्थक इसी अनुभव को उनकी संभावित दावेदारी का मजबूत पक्ष मानते हैं।

छात्र राजनीति से मिली नेतृत्व की पहली सीढ़ी-कमलेश शर्मा का सार्वजनिक जीवन केवल पत्रकारिता से शुरू नहीं हुआ, वे पीजी कॉलेज छात्रसंघ अध्यक्ष भी रह चुके हैं, छात्र राजनीति में अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालना उनके सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है,छात्र राजनीति में संगठन चलाने, विद्यार्थियों की समस्याओं को उठाने, प्रशासन के सामने अपनी बात रखने और विभिन्न समूहों के बीच समन्वय बनाने का अनुभव मिलता है,इसके बाद पत्रकारिता में लंबे समय तक सक्रिय रहने से उनके सार्वजनिक जीवन का दायरा और बढ़ा,समर्थकों का मानना है कि छात्र राजनीति और पत्रकारिता दोनों ने उन्हें अलग-अलग प्रकार का अनुभव दिया, एक ओर युवाओं और संगठन से जुड़ाव रहा, वहीं दूसरी ओर पत्रकारिता के कारण समाज के विभिन्न वर्गों और प्रशासनिक तंत्र से संवाद बना रहा, यदि वे भविष्य में चुनावी राजनीति में उतरते हैं तो यही अनुभव उनके लिए राजनीतिक पूंजी के रूप में काम कर सकता है।

भाजपा एनजीओ प्रकोष्ठ में प्रदेश कार्यसमिति सदस्य की जिम्मेदारी- कमलेश शर्मा को भाजपा एनजीओ प्रकोष्ठ का प्रदेश कार्यसमिति सदस्य बनाए जाने के बाद उनकी राजनीतिक सक्रियता को लेकर भी चर्चाएं बढ़ी हैं,प्रदेश स्तर पर संगठनात्मक जिम्मेदारी मिलना उनके समर्थकों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है,हालांकि किसी संगठनात्मक पद पर नियुक्ति को सीधे नगर पालिका अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी से जोड़ना उचित नहीं होगा,प्रत्याशी चयन राजनीतिक दल की अपनी प्रक्रिया,संगठन की राय,स्थानीय समीकरण और चुनावी रणनीति के आधार पर होता है,फिर भी स्थानीय राजनीति में यह चर्चा जरूर है कि प्रदेश संगठन से जुड़ाव ने कमलेश शर्मा की राजनीतिक पहचान को एक नया आयाम दिया है, अब सवाल यही है कि यदि पार्टी नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए ऐसे चेहरे पर विचार करती है,जिसका सामाजिक और सार्वजनिक क्षेत्र में संपर्क हो, तो क्या शर्मा का नाम संभावित सूची में ऊपर तक पहुंच पाएगा?

सामाजिक क्षेत्र में भी रही सक्रियता- कमलेश शर्मा की गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सामाजिक क्षेत्र से भी जुड़ा रहा है, उन्हें छत्तीसगढ़ प्रदेश रेडक्रॉस समिति, रायपुर के वाइस चेयरमैन तथा राज्य प्रबंध समिति छत्तीसगढ़ के सदस्य के रूप में जिम्मेदारी मिलने की बात सामने आती है, कोरिया जैसे क्षेत्र से प्रदेश स्तर की संस्था में जिम्मेदारी तक पहुंचना उनके सार्वजनिक जीवन की एक उल्लेखनीय उपलब्धि के रूप में देखा जाता है,रेडक्रॉस जैसी संस्था से जुड़ाव ने उन्हें सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों के साथ काम करने का अवसर दिया है,इसके अतिरिक्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरिया और लोक अदालत में सदस्य के रूप में कार्य करने का अनुभव भी उनके सार्वजनिक जीवन का हिस्सा रहा है, इन जिम्मेदारियों के कारण प्रशासन, सामाजिक संस्थाओं और आम लोगों से जुड़े विभिन्न स्तरों पर संवाद का अवसर उन्हें मिला।

मृदुभाषी छवि और व्यापक संपर्क को माना जा रहा मजबूत पक्ष- राजनीतिक चुनाव में संगठन के साथ-साथ व्यक्ति की व्यक्तिगत छवि भी महत्वपूर्ण होती है, कमलेश शर्मा को उनके समर्थक मृदुभाषी, व्यवहार कुशल और सहज व्यक्तित्व वाला चेहरा बताते हैं, स्थानीय राजनीति में यह गुण कई बार महत्वपूर्ण साबित होते हैं, अलग-अलग विचारधारा वाले लोगों के साथ संवाद बनाए रखना और व्यक्तिगत संबंधों को राजनीतिक मतभेद से अलग रखना किसी भी स्थानीय जनप्रतिनिधि के लिए उपयोगी माना जाता है, बैकुण्ठपुर जैसे नगर में व्यापारी, कर्मचारी, युवा, महिलाएं, सामाजिक संगठन, अधिवक्ता, पत्रकार, श्रमिक और ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े लोगों सहित विभिन्न वर्गों का अपना महत्व है, ऐसे में किसी भी संभावित दावेदार के लिए व्यापक सामाजिक संपर्क एक महत्वपूर्ण चुनावी पूंजी हो सकता है।

दोनों प्रमुख दलों में चर्चा का दावा- स्थानीय राजनीतिक चर्चाओं में कमलेश शर्मा के नाम को लेकर दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों के बीच भी चर्चा होने की बात कही जा रही है, हालांकि इस संबंध में अभी तक किसी दल की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, चुनाव से पहले संभावित प्रत्याशियों के नामों को लेकर इस तरह की चर्चाएं आम हैं, कई बार जिन नामों की चर्चा सबसे ज्यादा होती है, वे अंतिम सूची में नहीं होते और कई बार संगठन अचानक ऐसे चेहरे को सामने लाता है जिसकी चर्चा पहले कम होती है, इसलिए वर्तमान स्थिति में कमलेश शर्मा को संभावित दावेदार के रूप में देखना ही उचित होगा, अंतिम फैसला पार्टी की चुनावी रणनीति और अधिकृत घोषणा के बाद ही सामने आएगा।

क्या पत्रकारिता का अनुभव नगर पालिका में काम आएगा?- यदि कमलेश शर्मा चुनावी मैदान में उतरते हैं तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती पत्रकारिता से जनप्रतिनिधि की भूमिका में बदलाव की होगी, पत्रकारिता में व्यवस्था से सवाल पूछना एक भूमिका है, जबकि नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में उन्हीं व्यवस्थाओं के भीतर रहकर समस्याओं का समाधान कराना दूसरी जिम्मेदारी होगी, बैकुण्ठपुर नगर पालिका के सामने कई बुनियादी चुनौतियां हैं, सड़क, नाली, पेयजल, स्वच्छता, स्ट्रीट लाइट, कचरा प्रबंधन, यातायात, पार्किंग, नगर की साफ-सफाई, सार्वजनिक स्थानों का विकास और नागरिक सुविधाओं से जुड़े मुद्दे चुनाव में महत्वपूर्ण हो सकते हैं, ऐसे में यदि शर्मा की दावेदारी आगे बढ़ती है तो मतदाता यह भी जानना चाहेंगे कि शहर के विकास को लेकर उनका दृष्टिकोण क्या है।

अध्यक्ष पद केवल राजनीतिक प्रतिष्ठा नहीं, बड़ी प्रशासनिक जिम्मेदारी भी- नगर पालिका अध्यक्ष का पद स्थानीय राजनीति में महत्वपूर्ण माना जाता है, अध्यक्ष के सामने राजनीतिक अपेक्षाओं के साथ-साथ प्रशासनिक और वित्तीय जिम्मेदारियां भी होती हैं,नगर विकास के लिए आने वाली राशि का उपयोग, विकास कार्यों की प्राथमिकता,परिषद के सदस्यों के साथ समन्वय और नागरिकों की शिकायतों का निराकरण अध्यक्ष की कार्यशैली पर निर्भर करता है,इसलिए चुनावी चर्चा में किसी भी दावेदार की व्यक्तिगत लोकप्रियता के साथ उसकी प्रशासनिक समझ और विकास की स्पष्ट सोच भी महत्वपूर्ण होगी,यदि कमलेश शर्मा वास्तव में मैदान में उतरते हैं तो उनके सामने यही चुनौती होगी कि वे अपने लंबे सार्वजनिक अनुभव को नगर विकास के स्पष्ट एजेंडे में कैसे बदलते हैं।

बैकुण्ठपुर को किस तरह का नेतृत्व चाहिए?- नगर पालिका चुनाव में एक बड़ा सवाल यह भी रहेगा कि शहर के मतदाता किस तरह का नेतृत्व चाहते हैं, क्या मतदाता अनुभवी चेहरे को प्राथमिकता देंगे? क्या संगठन के पुराने कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा? क्या नया चेहरा सामने आएगा? क्या सामाजिक संपर्क वाला व्यक्ति पार्टी के पारंपरिक समीकरणों को बदल पाएगा? इन सवालों के जवाब चुनावी माहौल आगे बढ़ने के साथ सामने आएंगे, कमलेश शर्मा का नाम इसलिए चर्चा में है क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि पारंपरिक राजनीतिक कार्यकर्ता से कुछ अलग है, छात्र राजनीति, पत्रकारिता, सामाजिक संस्थाओं और संगठनात्मक जिम्मेदारियों का मिश्रण उन्हें अलग पहचान देता है।

टिकट तक पहुंचना पहली और चुनाव जीतना दूसरी चुनौती- राजनीतिक गलियारों में किसी नाम की चर्चा होना और पार्टी का टिकट मिलना दो अलग-अलग बातें हैं, टिकट के बाद भी चुनाव जीतना अलग चुनौती है, यदि किसी दल से कई दावेदार सामने आते हैं तो पार्टी के सामने स्थानीय गुटीय समीकरण, वार्डों की स्थिति, सामाजिक संतुलन, संगठन की राय और उम्मीदवार की जीत की संभावना जैसे कई पहलू होंगे, कमलेश शर्मा की संभावित दावेदारी में भी यही कसौटियां लागू होंगी, उनके समर्थक जहां जनसंपर्क और सार्वजनिक जीवन के अनुभव को ताकत मान रहे हैं, वहीं राजनीतिक विश्लेषण की नजर से यह देखना होगा कि संगठनात्मक स्तर पर उनकी स्वीकार्यता कितनी है और चुनावी मैदान में उनका प्रभाव किस हद तक दिखाई देता है।

शहर की समस्याएं बनेंगी असली चुनावी मुद्दा-बैकुण्ठपुर के नगर पालिका चुनाव में व्यक्तिगत दावेदारी से ज्यादा महत्वपूर्ण अंततः शहर के मुद्दे होंगे,शहर में नागरिक सुविधाओं की स्थिति, सड़क और नाली व्यवस्था, पेयजल, सफाई, कचरा निपटान, प्रकाश व्यवस्था और विकास कार्यों की गुणवत्ता जैसे विषय चुनावी चर्चा का हिस्सा बन सकते हैं, जो भी उम्मीदवार इन मुद्दों पर स्पष्ट और व्यावहारिक रोडमैप जनता के सामने रख पाएगा,उसकी दावेदारी को मजबूती मिल सकती है,यदि कमलेश शर्मा चुनाव लड़ते हैं तो उनके लिए भी केवल अपनी पहचान और अनुभव बताना पर्याप्त नहीं होगा, उन्हें यह बताना होगा कि अध्यक्ष बनने के बाद बैकुण्ठपुर के लिए उनकी नाम चर्चा में है,लेकिन उम्मीदवारी घोषित नहीं हुई है, उनका पत्रकारिता का अनुभव, छात्र राजनीति की पृष्ठभूमि,सामाजिक क्षेत्र में सक्रियता,विधिक सेवा से जुड़ा अनुभव और भाजपा एनजीओ प्रकोष्ठ में प्रदेश कार्यसमिति सदस्य की जिम्मेदारी उन्हें संभावित दावेदारों के बीच अलग पहचान जरूर देती है,लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष पद का चुनाव अंततः राजनीतिक संगठन, स्थानीय समीकरण और जनता के समर्थन से तय होगा,अब असली सवाल–क्या कमलेश शर्मा सिर्फ राजनीतिक चर्चा का चेहरा रहेंगे या चुनावी मैदान में उतरकर दावेदारी को हकीकत में बदलेंगे?

बैकुण्ठपुर की राजनीति में आने वाले महीनों में इस सवाल का जवाब तलाशा जाएगा। अनारक्षित अध्यक्ष पद ने राजनीतिक मैदान खोल दिया है,कई चेहरे अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं,ऐसे में कमलेश शर्मा का नाम भी फिलहाल उन चेहरों में शामिल है,जिस पर राजनीतिक नजरें टिक गई हैं,टिकट किसे मिलेगा, यह पार्टी तय करेगी,लेकिन जनता के बीच कौन स्वीकार्य है, इसका फैसला अंततः चुनावी मैदान ही करेगा।

दिसंबर तक बढ़ सकती है राजनीतिक सरगर्मी

जैसे-जैसे चुनाव का समय नजदीक आएगा,राजनीतिक गतिविधियां बढ़ने की संभावना है,संभावित दावेदारों के समर्थक सक्रिय होंगे,वार्ड स्तर पर संपर्क बढ़ेगा और राजनीतिक दल अपने-अपने स्तर पर समीकरणों का आकलन करेंगे,ऐसे में कमलेश शर्मा के नाम की चर्चा आने वाले दिनों में और तेज होती है या किसी अन्य चेहरे का नाम आगे निकलता है,यह देखना दिलचस्प होगा,फिलहाल उनके नाम को लेकर राजनीतिक चर्चा जरूर शुरू हो चुकी है,लेकिन अंतिम तस्वीर अभी बाकी है।

'चर्चा' से 'दावेदारी' तक का सफर बाकी- कमलेश शर्मा के मामले में फिलहाल स्थिति स्पष्ट है...

एनएच-130 पर चूल्हेट पुल के पास वैकल्पिक मार्ग बहा

तेज बहाव में पाइप भी कई मीटर दूर तक बहे,आवागमन बाधित होने से बढ़ा खतरा

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,23 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

सरगुजा में लगातार हो रही बारिश के बाद नदी-नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। इसका असर राष्ट्रीय राजमार्ग-130 पर भी देखने को मिला। चूल्हेट पुल के पास बनाया गया वैकल्पिक मार्ग नदी के तेज बहाव में बह गया। मार्ग में पानी की निकासी के लिए लगाए गए बड़े-बड़े पाइप भी तेज बहाव में कई मीटर दूर तक बह गए। जलस्तर बढ़ने और वैकल्पिक मार्ग के क्षतिग्रस्त होने से इस हिस्से में आवागमन प्रभावित हुआ है। तेज बहाव के कारण मौके पर हादसे का

खतरा भी बढ़ गया है। पुल के किनारे बनाए गए वैकल्पिक मार्ग के बह जाने से वाहनों की आवाजाही को लेकर परेशानी की स्थिति निर्मित हो गई है। बारिश जारी रहने से नदी का जलस्तर और बढ़ने की आशंका है। ऐसे में प्रशासन और संबंधित विभाग की टीम को मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेने तथा आवागमन को सुरक्षित बनाने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है।

बलरामपुर में यातायात नियमों की अनदेखी पर सख्ती...सवारी ढो रही पिकअप जब्त,दो पिकअप और ऑटो समेत तीन वाहनों पर 7 हजार का जुर्माना

-संवाददाता-

बलरामपुर,23 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

जिले में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने और सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए परिवहन विभाग ने यातायात नियमों के उल्लंघन के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। रविवार को राजपुर विकासखंड में मालवाहक पिकअप में यात्रियों को बैठाकर ले जाने का मामला सामने आया।पिकअप को मौके पर जब्त कर राजपुर थाने की अभिरक्षा में रखा गया।

मालवाहक वाहन में सवारी बैठाना पड़ा भारी : चेकिंग के

दौरान परिवहन विभाग की टीम ने मालवाहक वाहन का उपयोग यात्री परिवहन के लिए करते हुए एक पिकअप को पकड़ा।

यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े इस गंभीर उल्लंघन को देखते हुए वाहन को जब्त कर पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया।

तीन वाहनों से वसूला 7 हजार का जुर्माना : अभियान के दौरान अधिकारियों ने दो अन्य पिकअप और एक ऑटो को भी यातायात नियमों का उल्लंघन करते पकड़ा। तीनों वाहनों के खिलाफ

चालानी कार्रवाई करते हुए कुल 7 हजार रुपए का जुर्माना वसूला गया।

नियम तोड़े तो आगे भी होगी कार्रवाई : परिवहन विभाग ने वाहन चालकों को स्पष्ट संदेश दिया है कि मालवाहक वाहनों में यात्रियों का परिवहन किसी भी स्थिति में न करें। अधिकारियों ने कहा कि यात्रियों की जान जोखिम में डालने वाले और यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

CMYK

'फर्जी किसान, संदिग्ध खाते और करोड़ों का लेनदेन'

जामपारा समिति की फाइल खुली, प्रभाकर सिंह पर एफआईआर

- 13 पैक्स और 39 खातों की जांच में सामने आए संदिग्ध लेनदेन के संकेत, कृषि विभाग की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई, हाईकोर्ट के आदेश से पहले जांच की रफ्तार पर लगी थी रोक...
- जामपारा समिति में फर्जी धान खरीदी का मामला, प्रभाकर सिंह सहित 11 पर एफआईआर, दस्तावेजों में वित्तीय लेनदेन और किसान पंजीयन पर गंभीर सवाल...
- जांच प्रतिवेदन के आधार पर बैकुण्ठपुर थाने में दर्ज हुआ अपराध, समिति के प्रबंधन से लेकर बैंक खातों और भुगतान प्रक्रिया तक उठे सवाल, हाईकोर्ट के आदेश के बाद आगे की कार्रवाई प्रभावित

फर्जी पंजीयन, संदिग्ध खाते और करोड़ों का लेनदेन...जामपारा समिति पर जांच का शिकंजा

जामपारा समिति में धान खरीदी का 'खेल'! एफआईआर के बाद 11 और लोग जांच के दायरे में

20 साल की धान खरीदी पर उठे सवाल, फर्जी पंजीयन के मामले में प्रभाकर सिंह पर एफआईआर

-रवि सिंह-

बैकुण्ठपुर/कोरिया,23 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित जामपारा में धान खरीदी,किसान पंजीयन और समिति के वित्तीय संचालन को लेकर सामने आया विवाद अब आपराधिक प्रकरण तक पहुंच चुका है,उपलब्ध शासकीय दस्तावेजों के अनुसार जांच प्रतिवेदन के आधार पर समिति के तत्कालीन प्रबंधक प्रभाकर सिंह सहित 11 व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध दर्ज कराया गया है,बैकुण्ठपुर थाने में 15 नवंबर 2024 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने का उल्लेख विभागीय पत्र में है। मामला केवल धान खरीदी में कथित अनियमितता तक सीमित नहीं है,जांच से जुड़े दस्तावेजों में फर्जी किसान पंजीयन,समिति के खातों से होने वाले वित्तीय लेनदेन,कर्मचारियों के प्रभार में बदलाव, वेतन भुगतान और समिति की राशि के कथित दुरुपयोग जैसे कई बिंदु सामने आए हैं,एक अन्य दस्तावेज में भारतीय दंड संहिता की धारा 467, 468 और 471 के तहत अपराध घटित होना पाए जाने का उल्लेख भी किया गया है,हालांकि एफआईआर में नाम आने मात्र से किसी व्यक्ति को दोषी नहीं माना जा सकता,आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया में ही होगी,लेकिन सरकारी दस्तावेजों में दर्ज कार्रवाई यह जरूर बताती है कि जामपारा समिति का मामला विभागीय शिकायत से आगे बढ़कर पुलिस जांच के स्तर तक पहुंच चुका है।

जांच रिपोर्ट के बाद एफआईआर तक पहुंचा मामला

कलेक्टर कोरिया को भेजे गए विभागीय पत्र में आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित जामपारा में धान खरीदी से संबंधित जांच का उल्लेख है,पत्र के अनुसार तत्कालीन समिति प्रबंधक प्रभाकर सिंह तथा जांच प्रतिवेदन में उल्लेखित कुल 11 व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई के लिए आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के निर्देश दिए गए थे,इसके बाद संबंधित निर्देशों के पालन में 15 नवंबर 2024 को थाना बैकुण्ठपुर में प्रभाकर सिंह एवं अन्य 11 व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने की जानकारी विभाग ने दी, यहां एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि विभागीय स्तर पर पहले जांच हुई,उसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा,यानी कार्रवाई केवल किसी मौखिक शिकायत के आधार पर नहीं,बल्कि जांच प्रतिवेदन के संदर्भ में की गई बताई गई है, अब पुलिस के सामने यह स्पष्ट करना होगा कि जिन आरोपों के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई, उनमें प्रत्येक आरोपी की भूमिका क्या थी और कथित अनियमितता से उसका संबंध किस स्तर पर था।

समिति की राशि के इस्तेमाल पर भी उठे सवाल

जामपारा समिति के तत्कालीन प्रबंधक से संबंधित शिकायत में यह आरोप भी लगाया गया कि वित्तीय प्रभार से अलग किए जाने के बाद भी वेतन भुगतान किया गया, शिकायतकर्ता ने इसे समिति की राशि के दुरुपयोग से जोड़ते हुए जांच और राशि की वसूली की मांग की, दस्तावेज के अनुसार प्रभाकर सिंह को 8 जनवरी 2024 को समिति के वित्तीय प्रभार से अलग किया गया था, इसके बाद उन्हें धान खरीदी कार्य से हटाकर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की बैकुण्ठपुर शाखा से संबद्ध किए जाने का उल्लेख मिलता है,इसके बाद भी समिति के खाते से वेतन भुगतान किए जाने का आरोप सामने आया,इस आरोप की वास्तविकता जांच के बाद ही स्पष्ट होगी, इसके लिए वेतन बिल,भुगतान आदेश,बैंक स्टेटमेंट,सेवा संबंधी आदेश और संबंधित अवधि के उपस्थिति रिकॉर्ड का मिलान आवश्यक होगा।

20 साल की व्यवस्था में निगरानी किसकी थी?

इस पूरे प्रकरण का सबसे बड़ा प्रशासनिक सवाल शायद यही है,यदि शिकायतों के अनुसार प्रभाकर सिंह लंबे समय तक समिति के प्रबंधकीय कामकाज और धान खरीदी से जुड़े रहे,तो इतने लंबे समय में समिति का ऑडिट कैसे हुआ? धान खरीदी के रिकॉर्ड का परीक्षण किसने किया? किसान पंजीयन की जांच किस स्तर पर हुई? समिति के बैंक खातों की निगरानी किसने की? वर्षवार स्टॉक और भुगतान का मिलान किसने किया? और यदि अब जांच में गड़बड़ी सामने आती है तो यह भी देखा जाना चाहिए कि संबंधित समय में निरीक्षण करने वाले अधिकारियों की रिपोर्ट में क्या दर्ज था,क्योंकि किसी समिति में यदि वर्षों तक एक ही तरह की कथित अनियमितता चलती रही तो केवल अंतिम स्तर के कर्मचारी को जिम्मेदार ठहराने से पूरी तस्वीर सामने नहीं आएगी,निगरानी तंत्र की भूमिका भी जांच का हिस्सा बननी चाहिए।

प्रभार बदला,लेकिन विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ

8 जनवरी 2024 के आदेश में प्रभाकर सिंह को वित्तीय प्रभार से अलग किए जाने के साथ समिति के प्रबंधकीय कामकाज की जिम्मेदारी दूसरे व्यक्ति को दिए जाने का उल्लेख है,बाद में 16 नवंबर 2024 के संशोधित आदेश में समिति से जुड़े कर्मचारियों के कार्यस्थल और जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया। दस्तावेज में प्रभाकर सिंह को एफआईआर दर्ज होने के कारण धान खरीदी प्रभारी के कार्य से अलग करने तथा अन्य कर्मचारियों को अलग-अलग समितियों या खरीदी केंद्रों में जिम्मेदारी देने की व्यवस्था दर्ज है,इससे स्पष्ट है कि विभाग ने विवाद सामने आने के बाद समिति के संचालन और कर्मचारियों के प्रभार में बदलाव किया,लेकिन यह बदलाव अपने आप में पूर्व की कथित अनियमितताओं का निष्कर्ष नहीं है। उन आरोपों की पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया से ही होगी।

समिति के बैंक खातों में लाखों का लेनदेन,रिकॉर्ड संधारण पर भी सवाल...

सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं,बैकुण्ठपुर से संबंधित एक आदेश में समिति के बैंक खातों के लेनदेन का उल्लेख किया गया है,इसमें बचत खातों,शेयरधारिता खातों,कैश क्रेडिट ऋण खातों तथा अन्य बैंक खातों में जमा और आहरण की रकम दर्ज है,दस्तावेज में समिति के रिकॉर्ड और ऋण संबंधी दस्तावेजों के संधारण को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। रिकॉर्ड व्यवस्थित रूप से नहीं रखे जाने से सदस्यों को ऋण वितरण,ऋण अदायगी और समिति द्वारा किए गए खर्च की वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं होने की बात कही गई है,ऐसी स्थिति में जांच के लिए बैंक रिकॉर्ड महत्वपूर्ण हो जाता है,यदि किसी खाते से बड़ी रकम निकली है तो यह देखना होगा कि राशि किस उद्देश्य से निकाली गई,किसे भुगतान किया गया और संबंधित भुगतान का लेखा समिति के रिकॉर्ड में दर्ज है या नहीं।

प्रभाकर सिंह को लेकर पुलिस रिकॉर्ड में भी आपराधिक गतिविधियों का उल्लेख

जामपारा समिति से अलग एक पुलिस दस्तावेज में प्रभाकर सिंह के विरुद्ध पूर्व में दर्ज आपराधिक मामलों का उल्लेख किया गया है,पुलिस अधीक्षक कोरिया द्वारा जारी आदेश में उन्हें वर्ष 2004 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त बताए जाने का उल्लेख है,दस्तावेज में मारपीट,जान से मारने की धमकी तथा अन्य मामलों का जिक्र करते हुए उनके आचरण में सुधार नहीं होने की बात दर्ज की गई है,इसी आधार पर पुलिस रिकॉर्ड में उनके विरुद्ध निगरानी संबंधी कार्रवाई का उल्लेख है,यह दस्तावेज जामपारा समिति के धान खरीदी प्रकरण का प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है,इसलिए दोनों मामलों को एक ही घटना के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा,लेकिन यह जरूर स्पष्ट करता है कि पुलिस रिकॉर्ड में प्रभाकर सिंह के विरुद्ध पहले से आपराधिक मामले दर्ज होने का उल्लेख मौजूद था।

सबसे बड़ा सवाल...इतने समय तक निगरानी किसकी थी?

इस मामले में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सवाल भी सामने आता है, यदि समिति के प्रबंधन और धान खरीदी व्यवस्था में लंबे समय तक एक ही व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका रही और बाद में फर्जी किसान पंजीयन जैसे गंभीर आरोप सामने आए,तो संबंधित अवधि में समिति का नियमित ऑडिट और निरीक्षण किस स्तर तक हुआ? समिति के रिकॉर्ड की जांच किसने की? किसान पंजीयन का सत्यापन किस स्तर पर हुआ? धान खरीदी के बाद स्टॉक का मिलान किसने किया? समिति के बैंक खातों की निगरानी कैसे हुई? यदि रिकॉर्ड में कोई अनियमितता थी तो वह पहले क्यों नहीं पकड़ी गई? इन सवालों का जवाब केवल प्रभाकर सिंह या एफआईआर में नामित लोगों की जांच से नहीं मिलेगा,इसके लिए उस पूरी प्रशासनिक और सहकारी निगरानी व्यवस्था को भी देखना होगा जिसके तहत समिति काम कर रही थी।

अब जांच के लिए इन रिकॉर्ड का मिलान जरूरी

जामपारा प्रकरण की वास्तविक तस्वीर सामने लाने के लिए जांच एजेंसी को कई दस्तावेजों का आपस में मिलान करना होगा,सबसे पहले किसान पंजीयन रिकॉर्ड और संबंधित किसानों की वास्तविक भूमि का सत्यापन जरूरी होगा, इसके बाद पंजीकृत रकबे और खरीदी गई धान की मात्रा का मिलान होना चाहिए,इसके साथ ही समिति के धान खरीदी रजिस्टर,स्टॉक रजिस्टर,परिवहन रिकॉर्ड और भुगतान विवरण की भी जांच आवश्यक होगी,वित्तीय हिस्से में समिति के बैंक खातों से हुए लेनदेन,नकद आहरण, बैंक ट्रांसफर,वेतन भुगतान और अन्य खर्चों का परीक्षण महत्वपूर्ण होगा,यदि इन रिकॉर्डों में कोई विसंगति मिलती है तो उसके आधार पर संबंधित व्यक्ति की भूमिका तय की जा सकती है।

सिर्फ एफआईआर नहीं,पूरी व्यवस्था की जांच जरूरी-जामपारा समिति का मामला अब पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है,लेकिन इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जांच केवल एफआईआर में नामित व्यक्तियों तक सीमित रहने के बजाय पूरी प्रक्रिया की पड़ताल करना जरूरी है, यदि फर्जी किसान पंजीयन हुआ तो उसे स्वीकृत किसने किया? यदि धान खरीदी रिकॉर्ड में गड़बड़ी हुई तो सत्यापन किस स्तर पर हुआ? यदि समिति के खाते से राशि का गलत इस्तेमाल हुआ तो भुगतान किसकी अनुमति से हुआ? यदि वेतन भुगतान नियमों के विपरीत हुआ तो उसे स्वीकृत किसने किया? और यदि वर्षों तक समिति का संचालन इसी व्यवस्था में चलता रहा तो निरीक्षण और ऑडिट में यह सामने क्यों नहीं आया? इन सवालों के जवाब मिलने पर ही जामपारा प्रकरण की पूरी तस्वीर सामने आएगी।

467, 468 और 471 का उल्लेख क्यों महत्वपूर्ण?

जांच संबंधी दस्तावेज में भारतीय दंड संहिता की धारा 467,468 और 471 के अंतर्गत अपराध घटित होना पाए जाने की बात दर्ज है,इन धाराओं का संबंध गंभीर दस्तावेजी जालसाजी और जाली दस्तावेज के उपयोग जैसे अपराधों से रहा है,इसलिए यदि पुलिस जांच में दस्तावेजों की जालसाजी अथवा उनके इस्तेमाल की पुष्टि होती है तो मामला केवल वित्तीय अनियमितता तक सीमित नहीं रहेगा,हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि विभागीय दस्तावेज में धाराओं का उल्लेख और एफआईआर दर्ज होना आरोपों की स्थिति को दर्शाता है। अंतिम दोषसिद्धि अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर ही होगी।

हाईकोर्ट के आदेश से कार्रवाई पर फिलहाल प्रभाव

मामले से जुड़े दस्तावेज में यह भी उल्लेख है कि आरोपियों के संबंध में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई, न्यायालय द्वारा नो कोर्सिव एक्शन संबंधी आदेश दिए जाने के कारण आगे की कठोर कार्रवाई पर प्रभाव पड़ा,इसका मतलब यह नहीं है कि एफआईआर समाप्त हो गई या आरोप स्वतः निरस्त हो गए। न्यायालय का अंतरिम आदेश और आपराधिक प्रकरण की आगे की स्थिति अलग-अलग कानूनी विषय हैं,अब आगे की कार्रवाई इस बात पर भी निर्भर करेगी कि न्यायालय में मामले की स्थिति क्या रहती है और जांच एजेंसी को आगे बढ़ने की अनुमति किस सीमा तक मिलती है।

दस्तावेजों की जांच से तय होगी आरोपों की सच्चाई

फिलहाल उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर इतना स्पष्ट है कि जामपारा समिति से जुड़े मामले में विभागीय जांच हुई,उसके बाद प्रभाकर सिंह सहित 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और वित्तीय तथा प्रशासनिक स्तर पर भी कई सवाल उठाए गए,लेकिन इन आरोपों को अंतिम सत्य मानना उचित नहीं होगा,मामले में पुलिस जांच, न्यायालयीन प्रक्रिया और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर ही वास्तविक जिम्मेदारी तय होगी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जांच निष्पक्ष और दस्तावेज आधारित हो। किसान पंजीयन से लेकर बैंक खाते तक और धान खरीदी से लेकर भुगतान तक पूरी श्रृंखला की पड़ताल की जाए,जामपारा समिति की कहानी का असली सच एफआईआर में दर्ज आरोपों से नहीं,बल्कि उन दस्तावेजों के मिलान से सामने आएगा जिनके आधार पर किसान पंजीकृत हुए, धान खरीदा गया और समिति की राशि का लेनदेन हुआ,अब सवाल यह नहीं कि शिकायत हुई या एफआईआर दर्ज हुई। असली सवाल यह है कि फर्जी पंजीयन यदि हुआ तो किसने किया,धान खरीदी किस आधार पर हुई, राशि कहां गई और पूरी प्रक्रिया की निगरानी करने वाली व्यवस्था ने इसे समय रहते क्यों नहीं पकड़ा? इन सवालों के जवाब ही तय करेंगे कि जामपारा समिति में मामला केवल प्रशासनिक लापरवाही का था या इसके पीछे किसी बड़े वित्तीय और दस्तावेजी खेल की वास्तविकता भी सामने आती है।

ड्रंक एंड ड्राइव : बुलेट चालक पर 10 हजार रुपए का जुर्माना...शराब के नशे में वाहन चलाना पड़ा भारी,न्यायालय ने धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सुनाया फैसला

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,23 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सरगुजा पुलिस द्वारा वाहन चालकों के खिलाफ लगातार सख्ती की जा रही है। इसी अभियान के तहत यातायात पुलिस ने शराब के नशे में बुलेट चलाते एक युवक के खिलाफ कार्रवाई कर मामला न्यायालय में पेश किया, जहां न्यायालय ने चालक को 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल (भा.पु.से.) के निर्देशन में यातायात पुलिस टीम द्वारा नियमित वाहन जांच के दौरान बुलेट मोटरसाइकिल क्रमांक CG 15 EC 3460 को रोककर चालक से पूछताछ की गई। चालक ने अपना नाम कृष्ण कुमार सिंह,पिता कालिंदर सिंह, उम्र 27 वर्ष,निवासी दरिमा बताया। जांच के दौरान चालक के शराब के नशे में होने का संदेह होने पर ब्रेथ एनालाइजर से परीक्षण किया गया। परीक्षण में चालक द्वारा शराब का सेवन कर वाहन चलाना पाया गया। इसके बाद यातायात पुलिस ने उसके विरुद्ध धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर मामला माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने वाहन चालक को 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

सरगुजा पुलिस

सूरजपुर सहकारिता विभाग में आपका स्वागत है...!

जहां जांच भी होती है,कमी भी मिलती है,कमी भी मिट जाती है और फिर बहाली की तैयारी भी हो जाती है!

धान गायब हो तो चिंता मत करिए...जांच कीजिए...अगली जांच में धान भी मिल जाएगा!

-ओंकार पाण्डेय-

सूरजपुर,23 अगस्त 2026 (घटती-घटना)। अगर सहकारिता विभाग की कार्यप्रणाली पर कोई प्रशिक्षण संस्थान खुल जाए तो उसका पहला पाठ शायद यही होगा–'घबराइए मत,हर कमी की दूसरी जांच होती है।'और यदि दूसरी जांच भी हो जाए,तो पहली जांच को भूल जाइए। आखिर व्यवस्था का अपना गणित है, जिले के सहकारी तंत्र में वर्षों से कुछ नाम चर्चा में रहते हैं,भैयाथान शाखा के अंतर्गत संचालित कुछ समितियां और धान खरीदी केंद्र हर खरीदी सीजन में किसी न किसी वजह से सुर्खियों में आ जाते हैं,किसान बदलते हैं,मौसम बदलता है,लेकिन चर्चा के पात्र कम ही बदलते हैं।

2025 की धान खरीदी...जहां गणित भी शर्मिंदा हो जाए–कहा जाता है कि गणित कभी झूठ नहीं बोलता,लेकिन 2025 की धान खरीदी ने शायद गणित को भी सोचने पर मजबूर कर दिया,चर्चाएं हुईं कि कहीं रिकॉर्ड में धान ज्यादा था और गोदाम में कम,फिर जांच हुई,जांच में कमी मिली,इसके बाद फिर जांच हुई,और फिर वही कमी...पता नहीं कैसे...पूरी भी हो गई,यदि यह किसी जादूगर का शो होता तो दर्शक ताली बजाते,लेकिन यह सरकारी धान खरीदी थी,इसलिए जनता ने सवाल पूछे।

टीमें आईं... रिपोर्ट बनी... फिर सब सामान्य!

तहसीलदार आए,एसडीएम आए,सहकारिता विभाग की टीमें आईं,निरीक्षण हुआ,रिपोर्ट बनी,और फिर धीरे-धीरे ऐसा सन्नाटा छा गया मानो कुछ हुआ ही न हो,यदि पहली रिपोर्ट गलत थी तो उसे बनाने वालों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए थी,यदि पहली रिपोर्ट सही थी तो दूसरी रिपोर्ट के आधार क्या थे? यही वह प्रश्न हैं जिनका उत्तर सार्वजनिक होना चाहिए।

निलंबन भी हुआ... अब बहाली भी होगी?

उस समय कुछ समिति प्रबंधकों और धान खरीदी केंद्र प्रभारियों पर कार्रवाई हुई,अब चर्चा यह है कि वही लोग फिर से आगामी धान खरीदी में जिम्मेदारी संभाल सकते हैं,यदि ऐसा होता है तो जनता पूछ रही है–क्या निलंबन केवल औपचारिकता था? यदि दोषी थे तो बहाली क्यों? यदि दोषी नहीं थे तो निलंबन क्यों?

शिवप्रसादनगर : जहां सवाल अभी खत्म नहीं हुए...

शिवप्रसादनगर धान खरीदी केंद्र को लेकर भी वर्षों से चर्चाएं होती रही हैं, स्थानीय स्तर पर अनियमितताओं के आरोप लगाए गए,कुछ लोगों ने संपत्ति खरीद को लेकर भी प्रश्न उठाए,यदि शिकायतें निराधार थीं तो उन्हें स्पष्ट रूप से खारिज क्यों नहीं किया गया? यदि शिकायतें गंभीर थीं तो उनकी जांच का परिणाम सार्वजनिक क्यों नहीं हुआ? नाम भी चर्चा में,लेकिन जवाब कौन देगा? स्थानीय चर्चाओं में साधना,हदीस और सोहराब जैसे नाम बार-बार लिए जाते रहे हैं।

धान खुद चलकर आया या जवाब अभी बाकी है?–सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि कमी मिली थी या नहीं,सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि पहली जांच सही थी तो बाद में स्टॉक कैसे पूरा हो गया? क्या धान रातों-रात उग आया? क्या गोदामों में कोई चमत्कार हुआ? या फिर किसी ने कम दाम में धान खरीदकर सरकारी रिकॉर्ड से हिसाब बराबर कर दिया? इन सवालों के जवाब जनता आज भी तलाश रही है।

बड़े अधिकारी क्या केवल दर्शक थे?–जब पूरा मामला चर्चा में था,तब प्रशासनिक जिम्मेदारी वाले पदों पर संभागीय आयुक्त सुनील तिवारी,प्रभारी उप आयुक्त सहकारिता अनिल कुमार बनज,जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अंबिकापुर के सीईओ श्रीकांत चंद्राकर और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अंबिकापुर के अध्यक्ष रामकिशन सिंह कार्यरत थे,सवाल यह नहीं कि वे दोषी हैं,सवाल यह है कि जब शिकायतें थीं,जांच थी और कार्रवाई भी हुई,तब उनकी निगरानी में अंतिम परिणाम क्या निकला? यदि सब कुछ नियमों के अनुसार हुआ तो जनता को पूरा रिकॉर्ड दिखाया जाए।

बैंक अध्यक्ष की पात्रता पर भी चर्चा...

जनचर्चा में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अंबिकापुर के अध्यक्ष रामकिशन सिंह की पात्रता को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं,इन चर्चाओं पर किसी सक्षम प्राधिकारी का अंतिम सार्वजनिक निर्णय उपलब्ध नहीं है, ऐसे में पारदर्शिता के हित में यह स्पष्ट होना चाहिए कि यदि शिकायतें हुई थीं तो उनका निस्तारण किस प्रकार किया गया।

और अब नई बाजी...

सोनपुर समिति में बोर्ड की शक्तियों में बदलाव के बाद फिर चर्चा शुरू हो गई है,लोग कह रहे हैं–सहकारिता विभाग में फाइलें नहीं चलतीं,शतरंज की चालें चलती हैं,यह केवल जनचर्चा है,लेकिन यदि ऐसी धारणा बन रही है तो उसे दूर करना भी विभाग की जिम्मेदारी है।

अब जनता व किसान का सवाल....

- जांच हुई तो रिपोर्ट कहां है?
- कमी मिली थी तो दोषी कौन?
- दोषी नहीं थे तो कार्रवाई क्यों?
- कार्रवाई हुई थी तो बहाली किस आधार पर?
- और यदि सब कुछ ठीक था,तो हर साल वही केंद्र और वही नाम चर्चा में क्यों आते हैं?

दैनिक घटती-घटना की मांग...

इन सभी प्रश्नों का समाधान केवल एक स्वतंत्र,निष्पक्ष और दस्तावेज आधारित जांच से ही संभव है,यदि शिकायतें निराधार हैं तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को सार्वजनिक रूप से क्लीन चिट मिले, यदि शिकायतों में तथ्य हैं,तो जिम्मेदारी केवल निचले स्तर तक सीमित न रहकर पूरी प्रशासनिक श्रृंखला की भी जांच होनी चाहिए।

वन विभाग की नाक के नीचे रेत माफियाओं का खेल! चिरमिरी वन परिक्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन का आरोप

मेरो-आमाडांड-मुकुंदपुर से छोटे डंपरों में रेत परिवहन की चर्चा,विभागीय अधिकारियों की भूमिका पर उठे सवाल

-राजेन्द्र शर्मा-

खड़गवां,23 अगस्त 2026 (घटती-घटना)। चिरमिरी वन परिक्षेत्र के मेरो,आमाडांड और मुकुंदपुर क्षेत्र में कथित अवैध रेत उत्खनन और परिवहन को लेकर सवाल उठने लगे हैं,स्थानीय ग्रामीणों और सूत्रों का आरोप है कि इन क्षेत्रों में लंबे समय से रेत का अवैध उत्खनन कर छोटे डंपरों के माध्यम से मनेंद्रगढ़ और चिरमिरी की ओर परिवहन किया जा रहा है, आरोप यह भी है कि लगातार वाहनों की आवाजाही के बावजूद संबंधित विभाग की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि वन क्षेत्र से प्रतिदिन रेत से लदे वाहन निकल रहे हैं तो संबंधित विभाग और मैदानी अमले की नजर उन पर क्यों नहीं पड़ रही? कार्रवाई के अभाव को लेकर अब विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं,हालांकि अवैध उत्खनन और किसी अधिकारी की संलिप्तता से जुड़े आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है।

कार्रवाई नहीं होने से संरक्षण की चर्चा–स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि मेरो,आमाडांड और मुकुंदपुर क्षेत्र में रेत का अवैध कारोबार लंबे समय से चल रहा है,ग्रामीणों के मुताबिक छोटे डंपरों के जरिए रेत का परिवहन किए जाने के कारण यह गतिविधि लगातार जारी रहने की बात सामने आ रही है,ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि यह परिवहन अवैध है तो अब तक जिम्मेदार विभाग ने इसे रोकने के लिए ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की? ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि कार्रवाई के अभाव के पीछे किसी स्तर पर संरक्षण हो सकता है,हालांकि इस संबंध में किसी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ अभी कोई प्रमाण सार्वजनिक नहीं हुआ है,ग्रामीणों ने पूरे मामले की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है,ताकि वास्तविक स्थिति सामने आ सके।

गरीब हितग्राहियों पर सख्ती,रेत परिवहन पर नरमी?– ग्रामीणों ने विभागीय कार्रवाई को लेकर असमानता के आरोप भी लगाए हैं, उनका कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य निर्माण कार्यों के लिए क्रेशर से गिट्टी अथवा निर्माण सामग्री लेकर जाने वाले वाहनों को कई बार रोककर पूछताछ किए जाने की शिकायतें सामने आती हैं,दूसरी ओर,रेत से भरे छोटे डंपरों के लगातार आवागमन को लेकर सवाल उठ रहे हैं,ग्रामीणों का कहना है कि यदि नियम सभी के लिए समान हैं तो कार्रवाई भी समान रूप से होनी चाहिए,गरीब हितग्राहियों के निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाली सामग्री की जांच और अवैध रेत परिवहन पर कार्रवाई के बीच कथित अंतर को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं।

कथित लेन-देन की चर्चाओं ने बढ़ाई गंभीरता–

मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर कुछ वाहन संचालकों और संबंधित लोगों के बीच कथित लेन-देन की चर्चाएं भी सामने आने का दावा किया जा रहा है,यदि भविष्य में जांच के दौरान ऐसे आरोप प्रमाणित होते हैं तो मामला केवल अवैध रेत उत्खनन और परिवहन तक सीमित नहीं रहेगा।

साइबर ठगी और सड़क हादसों से बचने युवाओं को किया जागरूक

एसपी हरीश राठौर ने कहा...जरा सी ऑनलाइन लापरवाही जीवनभर की कमाई छीन सकती है,यातायात में छोटी चूक परिवार के अरमानों पर डाल सकती है असर

-संवाददाता-

पटना/कोरिया,23 अगस्त 2026 (घटती-घटना)। जिले में साइबर अपराध और सड़क दुर्घटनाओं से बचाव को लेकर चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के तहत पंडित ज्वाला प्रसाद उपाध्याय शासकीय महाविद्यालय,पटना में साइबर एवं यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक हरीश राठौर ने छात्र-छात्राओं को ऑनलाइन ठगी से बचने के उपायों के साथ-साथ यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया। प्रदेश में चलाए जा रहे व्यापक साइबर जागरूकता अभियान के तहत 14 अगस्त से 2 अक्टूबर तक जिलेभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया और पुलिस अधिकारियों से साइबर सुरक्षा एवं सड़क सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की।

जरा सी लापरवाही पड़ सकती है भारी–कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एसपी हरीश राठौर ने कहा कि वर्तमान समय में जीवन की अधिकांश गतिविधियां ऑनलाइन माध्यम से जुड़ गई हैं, ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति को डिजिटल दुनिया में बेहद सतर्क रहने की जरूरत है, उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि साइबर मामलों में जरा सी लापरवाही जीवनभर की गाढ़ी कमाई छीन सकती है,जबकि यातायात में छोटी सी लापरवाही व्यक्ति और उसके परिवार के अरमानों को अधूरा कर सकती है, एसपी ने युवाओं से स्वयं जागरूक रहने के साथ अपने परिवार और आसपास के लोगों को भी साइबर अपराध एवं सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने की अपील की।

OTP, PIN और संदिग्ध लिंक से रहें सावधान–पुलिस अधीक्षक ने ऑनलाइन ठगी के विभिन्न तरीकों की जानकारी देते हुए विद्यार्थियों को फर्जी लिंक,APK फाइल,व्हाट्सऐप वीडियो कॉल और अनधिकृत तरीके से ओटीपी साझा करने के खतरों से सावधान किया, उन्होंने कहा कि किसी अनजान व्यक्ति के साथ OTP,PIN,पासवर्ड,बैंक खाते की जानकारी अथवा अन्य गोपनीय जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए,उन्होंने विद्यार्थियों को सलाह दी कि किसी अज्ञात लिंक पर क्लिक करने या संदिग्ध APK फाइल डाउनलोड करने से बचें,किसी भी ऑनलाइन लेन-देन में जल्दबाजी करने के बजाय पहले पूरी जानकारी की पुष्टि करें।

ठगी होने पर तुरंत 1930 पर करें शिकायत–कार्यक्रम में विद्यार्थियों को साइबर ठगी की स्थिति में तत्काल सहायता के लिए साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 की जानकारी दी गई, पुलिस ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति ऑनलाइन ठगी का शिकार होता है तो उसे बिना समय गंवाए 1930 पर शिकायत दर्ज करनी चाहिए,समय पर शिकायत मिलने से ठगी गई रकम को रोकने और आगे की कार्रवाई का प्रयास किया जा सकता है।

सड़क सुरक्षा को लेकर भी किया जागरूक–कार्यक्रम में यातायात नियमों की जानकारी देते हुए विद्यार्थियों को ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही वाहन चलाने,दोपहिया वाहन पर हेलमेट और चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया,इसके अलावा निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने,वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करने तथा यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई,पुलिस अधिकारियों ने विद्यार्थियों को समझाया कि सड़क पर थोड़ी सी सावधानी न केवल स्वयं की बल्कि अन्य लोगों की जिंदगी भी सुरक्षित रख सकती है।

घायल की मदद करना भी जिम्मेदारी–कार्यक्रम के दौरान गुड सेमेरिटन यानी नेक इंसान नीति की जानकारी भी विद्यार्थियों को दी गई,पुलिस ने सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की तत्काल मदद करने और उसे समय पर अस्पताल पहुंचाने के लिए प्रेरित किया, अधिकारियों ने कहा कि दुर्घटना के बाद समय पर मिलने वाली चिकित्सा किसी व्यक्ति की जान बचा सकती है,विद्यार्थियों को राहवीर एवं नगदी रहित उपचार योजना की जानकारी भी दी गई,ताकि सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को समय पर सहायता उपलब्ध कराने में समाज की भूमिका मजबूत हो सके।

सेल्फी के जरिए भी दिया जागरूकता संदेश–कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय परिसर में साइबर जागरूकता संबंधी स्टैंडी के सामने विद्यार्थियों और स्टाफ ने सेल्फी ली,इसके बाद इसे सोशल मीडिया पर साझा कर साइबर सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति जागरूकता का संदेश प्रसारित किया गया,कार्यक्रम को जिला युवा अधिकारी चहल कैलाशिया एवं उप पुलिस अधीक्षक श्याम मधुकर ने भी संबोधित किया,उन्होंने युवाओं से साइबर अपराधों के प्रति सतर्क रहने और यातायात नियमों का पालन कर स्वयं तथा दूसरों के जीवन को सुरक्षित रखने की अपील की, कार्यक्रम की शुरुआत महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. शिव शंकर राजवाड़े द्वारा एसपी हरीश राठौर के पुष्पगुच्छ से स्वागत के साथ हुई,कार्यक्रम के समापन पर महाविद्यालय परिवार की ओर से अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर थाना प्रभारी पटना प्रमोद पांडेय,प्रधान आरक्षक सत्येंद्र तिवारी,महिला प्रधान आरक्षक गीता टोप्पो, यातायात हवलदार डॉ. महेश मिश्रा, सहायक प्राध्यापक डॉ. बरखा सिंह,पूनम टोप्पो,सहायक ग्रेड-1 रोहित साहू सहित महाविद्यालय के अतिथि व्याख्याता और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन दुर्गावती राजवाड़े ने किया।

ये रिश्ता क्या कहलाता है में मायरा की चाल का हुआ खुलासा

अरमान-कबीर के बीच बढ़ी गलतफहमी

लोकप्रिय टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान-अभिरा की जिंदगी में गलतफहमियां और अजीब मोड़ तब आते हैं,जब उनकी बेटी मायरा उनसे बातें छिपाने लगती है। कहानी में आगे देखने को मिलेगा कि अरमान-अभिरा खुशी-खुशी फायरफ्लाई इवेंट का मजा लेते हैं। वहां अभिरा को एहसास होता है कि उनके बीच प्यार अभी भी जिंदा है और अरमान वादा करता है कि वह हमेशा उसकी जिंदगी को रोशनी से भरा रखेगा। दोनों अपनी जिंदगी में खुश रहने की कोशिश करते हैं और मायरा-मुक्ती को बुरी नजर से बचाने के लिए भी संघर्ष करते हैं।

अरमान-कबीर में हुई लड़ाई

अरमान-अभिरा डेट पर जाते हैं, लेकिन उनका रोमांटिक पल तब खराब हो जाता है, जब अरमान और कबीर के बीच गलतफहमी हो जाती है। लड़कियों को परेशान करने के शक में उनके बीच लड़ाई हो जाती है। अंधेरे की वजह से वे एक-दूसरे को पहचान नहीं पाते, लेकिन जैसे ही लाइट आती है कबीर अरमान को धक्का देकर भाग जाता है। इस बीच कहानी में आगे देखने को मिलता है कि कावेरी कहती है कि जब अरमान को ट्यूमर हुआ था तो उन्होंने खुशी-खुशी जन्माष्टमी मनाने का संकल्प लिया था। वह इस साल इसका आयोजन करने का फैसला करती हैं। पंडित जी कहते हैं कि वह पोद्दार परिवार को इस बार जन्माष्टमी आयोजित करने की अनुमति नहीं दे सकते। कावेरी पूछती हैं कि यह मौका किसने लिया। पोद्दार परिवार को पता चलता है कि दमानी परिवार ने यह मौका ले लिया है।

अभिरा ने मायरा को रंगे हाथों पकड़ा

मायरा यह देखकर चौंक जाती है कि अरमान-अभिरा वहां मौजूद हैं और हड़बड़ी में भागने लगती है,लेकिन अभिरा उसे देख लेती है। हैरानी की बात है कि अरमान, अभिरा को कबीर का नाम नहीं बताता और कबीर भी अपने परिवार के सामने यह बात छिपा लेता है कि अरमान ने उसे मारा था। इस बार मायरा और मुक्ति को बिना बताए रात में बाहर निकलने के लिए अभिरा के गुस्से का सामना करना पड़ता है। अभिरा, मायरा से फायरफ्लाई फेस्टिवल में जाने के बारे में पूछती है। मायरा उसे बताती है कि उसने सच क्यों छिपाया था। अभिरा मायरा को डांटती है। मायरा उसे बताती है कि मुक्ति को सच पता था। अभिरा मायरा और मुक्ति दोनों को डांटती है। मुक्ति मायरा से कहती है कि उसकी वजह से उसे भी डांट पड़ रही है। दोनों को एहसास होता है कि अभिरा को इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि कबीर भी फेस्टिवल में था और अरमान उसके साथ हुई अपनी मुठभेड़ के बारे में सच छिपा रहा है। मायरा और मुक्ति पहले अभिरा को मनाने का फैसला करती हैं।

एक ट्विस्ट बदल देगा कहानी

अभिरा, मायरा से बहुत नाराज दिखाई देती है, क्योंकि उसने सच छिपाया और कभी अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा। भले ही अभी मामला सुलझता हुआ दिख रहा है, लेकिन अरमान-अभि रा के बीच के राज आगे चलकर एक बड़े ट्विस्ट में बदलेंगे। असली राज यह है कि क्या अरमान सच में कबीर को माफ कर देगा या फिर कुछ और ही चल रहा है।

खतरों के खिलाड़ी 15 के सेट पर रोईं फरहाना भट्ट

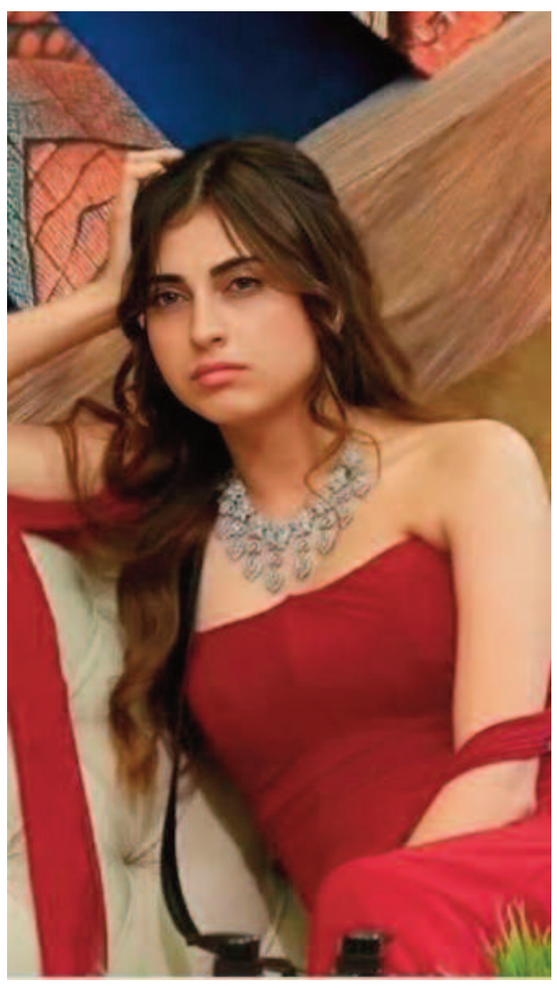

रोहित शेट्टी के स्टंट बेस्ड रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 15 में हर दिन नए ट्विस्ट और चुनौतियां देखने को मिल रही हैं। शो में शामिल कंटेस्टेंट्स खतरनाक स्टंट के साथ-साथ मानसिक दबाव का भी सामना कर रहे हैं। इसी बीच कंटेस्टेंट फरहाना भट्ट का एक इमोशनल मोमेंट चर्चा में आ गया है। शो के सेट से सामने आए वीडियो और प्रोमो में फरहाना भट्ट रोती हुई नजर आईं, जिसके बाद फैंस के बीच सवाल उठने लगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मजबूत मानी जाने वाली फरहाना भावुक हो गईं? क्या वह शो छोड़ने का फैसला करने वाली हैं? फरहाना भट्ट को शुरुआत से ही शो की मजबूत खिलाड़ियों में गिना जा रहा है। वह मुश्किल स्टंट करने से पीछे नहीं हटतीं और कई बार अपने आत्मविश्वास से बाकी कंटेस्टेंट्स को भी प्रभावित कर चुकी हैं। लेकिन खतरों के खिलाड़ी जैसे शो में डर और दबाव के बीच भावनाएं भी कई बार सामने आ जाती हैं। फरहाना का रोना भी इसी चुनौतीपूर्ण सफर का हिस्सा माना जा रहा है।

स्टंट के दौरान छलके आंसू

रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के मुताबिक, फरहाना एक मुश्किल टास्क के दौरान भावुक हो गईं। इस शो में कंटेस्टेंट्स को ऊंचाई, पानी, डरावने जानवरों और कई तरह की शारीरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे स्टंट के दौरान कई बार खिलाड़ी मानसिक रूप से दबाव महसूस करने लगते हैं। फरहाना के लिए भी यह सफर आसान नहीं रहा है। उन्होंने कई मौकों पर अपने डर का सामना करते हुए स्टंट पूरे किए हैं। लेकिन हर खिलाड़ी की तरह उनके लिए भी कुछ पल ऐसे आए, जब भावनाएं हावी हो गईं।

क्या फरहाना छोड़ रही हैं शो?

फरहाना के रोने के बाद सोशल मीडिया पर यह चर्चा तेज हो गई कि शायद वह शो छोड़ सकती हैं। हालांकि अभी तक ऐसी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है कि फरहाना भट्ट ने शो छोड़ने का फैसला लिया है। सिर्फ भावुक होने या रोने का मतलब यह नहीं होता कि कोई कंटेस्टेंट मुकाबले से बाहर हो रहा है। रियलिटी शो में कई बार खिलाड़ी तनाव, डर या किसी खास परिस्थिति के कारण भावुक हो जाते हैं और फिर अगले टास्क में वापसी करते हैं।

पहले भी दिखा चुकी हैं दमदार प्रदर्शन

फरहाना भट्ट ने शो में अपनी अलग पहचान बनाई है। वह अपनी बेबाक राय और मजबूत व्यक्तित्व के लिए जानी जाती हैं। खतरों के खिलाड़ी 15 में भी उन्होंने कई बार खुद को साबित किया है। शो के दौरान उनकी दूसरे कंटेस्टेंट्स के साथ बहस और फिर स्टंट में शानदार प्रदर्शन भी चर्चा में रहा है। उनके फैंस का मानना है कि फरहाना आसानी से हार मानने वाली खिलाड़ी नहीं हैं। उनका इमोशनल होना कमजोरी नहीं बल्कि इस मुश्किल सफर का एक हिस्सा है।

शो में भावनात्मक पल आम

खतरों के खिलाड़ी सिर्फ खतरनाक स्टंट का शो नहीं है, बल्कि यह कंटेस्टेंट्स की मानसिक मजबूती की भी परीक्षा लेता है। कई बार खिलाड़ी अपने परिवार को याद करके,डर का सामना करते हुए या लगातार दबाव के कारण भावुक हो जाते हैं। इस सीजन में भी कई कंटेस्टेंट्स ने बताया है कि शो का अनुभव उनके लिए भावनात्मक और चुनौतीपूर्ण रहा है। कठिन स्टंट के साथ खुद पर विश्वास बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है। फरहाना भट्ट के रोने वाला वीडियो सामने आने के बाद उनके फैंस सोशल मीडिया पर उनका समर्थन कर रहे हैं।

बेटे के लिए घर-घर काम मांगने गया सुरेश ओबेरॉय ने बताया

कि कैसे हुआ विवेक ओबेरॉय का डेब्यू,आरजीव्ही को मनाने के लिए बेले पापड़

सुरेश ओबेरॉय ने बताया कि कैसे बेटे विवेक ओबेरॉय के डेब्यू के लिए वह उनकी तस्वीरें लेकर फिल्ममेकर्स के घर जाते थे। इसी दौरान उन्होंने ये भी बताया कि कंपनी में कास्टिंग से पहले राम गोपाल वर्मा ने उनकी (विवेक ओबेरॉय) एक्टिंग का टेप कैसे देखा था।

विवेक ओबेरॉय इन दिनों नितेश तिवारी की मेगा बजट फिल्म रामायण को लेकर चर्चा में हैं,जिसमें वह विद्युत जिह्वा का किरदार निभा रहे हैं। हाल ही में ऐसी भी खबरें आईं कि विवेक ओबेरॉय रामायण के लिए मिली अपनी पूरी फीस कैंसर पीड़ित बच्चों को दान करेंगे। हालांकि, ये पहली बार नहीं है जब वह इस तरह की खबरों को लेकर चर्चा में हैं,पहले भी कई बार विवेक अपनी दरियादिली को लेकर सुर्खियां बटोर चुके हैं। विवेक ओबेरॉय को फिल्मी दुनिया में 2 दशक से ज्यादा का समय हो गया है। उन्होंने 2002 में राम गोपाल वर्मा की फिल्म कंपनी से बॉलीवुड डेब्यू किया था। इस फिल्म में उन्होंने गैंगस्टर चंद्रकांत उर्फ चंदू नागरे का रोल निभाया था,जिसके लिए उन्हें काफी तारीफ मिली थी। इस बीच अभिनेता के पिता और दिग्गज एक्टर सुरेश ओबेरॉय ने उस मेहनत के बारे में बात की जो विवेक को उनका पहला बड़ा मौका दिलाने में लगी थी।

विवेक ओबेरॉय के डेब्यू के लिए कई फिल्ममेकर्स के पास गए सुरेश ओबेरॉय

दिग्गज अभिनेता ने निधि वंसदानी के यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए बताया कि कैसे वह विवेक की तस्वीरें लेकर फिल्ममेकर्स के पास जाते थे और उन्हें एक मौका देने के लिए लोगों से बात करते थे। ये कुछ वैसा ही था, जैसे उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों में खुद के लिए किया था। सुरेश ओबेरॉय कहते हैं कि विवेक का फिल्म में आने का मतलब था एक बार फिर संघर्ष, लेकिन इस बार अपने बेटे के लिए। सुरेश ओबेरॉय ने बेटे विवेक के डेब्यू के बारे में बात करते हुए कहा-मुझे उसके लिए काफी संघर्ष करना पड़ा, मैं उसके लिए फिल्ममेकर्स के घर जाता था। ठीक वैसे ही, जैसे मैं अपनी तस्वीरें लेकर जाता था।

विवेक ओबेरॉय को कैसे मिली कंपनी फिल्म?

सुरेश ओबेरॉय उन दिनों राम गोपाल वर्मा के साथ किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जब उन्हें कंपनी का पता चला। उन्होंने कंपनी में विवेक को कास्ट करने के लिए राम गोपाल वर्मा से बात की, लेकिन आरजीवी विवेक को कास्ट करने से पहले ये देखना चाहते थे कि एक एक्टर के तौर पर वह काम कर सकते हैं या नहीं। विवेक के पास उनके एक्टिंग इंस्टीट्यूट की एक रिकॉर्डिंग थी, जिसे सुरेश ओबेरॉय ने राम गोपाल वर्मा को दिखाया। आरजीवी वो टेप देखने सुरेश ओबेरॉय के घर गए और विवेक की एक्टिंग से काफी प्रभावित हुए और आखिरकार कंपनी विवेक की डेब्यू फिल्म बन गई। इस क्राइम ड्रामा फिल्म में विवेक के साथ अजय देवगन, मनीषा कोइराला, मोहनलाल और अंतरा माली भी थे।

कंपनी में विवेक को देखकर सुरेश भावुक हो गए

सुरेश ओबेरॉय ने बताया कि अपने बेटे को पहली बार स्क्रीन पर देखकर इतने भावुक हो गए कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। हालांकि, उन्होंने ये भी बताया कि कंपनी में विवेक की परफॉर्मेंस उनकी पसंदीदा परफॉर्मेंस नहीं है। एक एक्टर के तौर पर विवेक उन्हें 2002 की रोमांटिक फिल्म साथिया में सबसे अच्छे लगे, जो कंपनी के कुछ महीने बाद रिलीज हुई थी। वर्कफ्रंट की बात करें तो विवेक ओबेरॉय आखिरी बार रोहित शेट्टी की ओटीटी एक्शन सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स और मस्ती 4 में नजर आए थे। अब वह नितेश तिवारी की रामायण में नजर आएंगे, जो भारत में दिवाली के मौके पर और दुनियाभर में 6 नवंबर को रिलीज होगी।

खेल समाचार

चैंपियन कर्ण शर्मा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास

नई दिल्ली ,23 अगस्त 2026। भारतीय क्रिकेट के अनुभवी लेग स्पिनर कर्ण शर्मा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। 38 वर्षीय कर्ण शर्मा ने यूपीटी 20 लीग 2026 के दौरान अपने लंबे क्रिकेट करियर को विराम दिया। उन्होंने करीब दो दशक तक घरेलू और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में योगदान दिया। कर्ण शर्मा ने यह घोषणा उस समय की जब वह कानपुर सुपरस्टार्स की ओर से यूपी टी20 लीग में खेल रहे थे। उन्होंने कहा कि वह अपना आखिरी पेशेवर मुकाबला खेलकर क्रिकेट के मैदान से विदाई लेंगे।

टीम इंडिया में चयन पर सारांश का बयान:सपना सच हो गया

कोलंबो,23 अगस्त 2026। घरेलू क्रिकेट में सालों की कड़ी मेहनत के बाद श्रीलंका के खिलाफ़ दूसरे मैच में टेस्ट डेब्यू करने वाले ऑफ़-स्पिन ऑलराउंडर सारांश जैन ने अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा से अपनी टेस्ट कैप मिलने के बाद भगवान और अपने परिवार का शुक्रिया अदा किया। बाएं हाथ के रिस्ट-स्पिनर कुलदीप यादव की जगह प्लेइंग इलेवन में शामिल हुए सारांश को टॉस से पहले टीम की मीटिंग में टेस्ट कैप नंबर 320 दी गई। रविवार को बी सी सीआई के सोशल मीडिया चैनलों पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में सारांश ने कहा, जब भी कोई खिलाड़ी क्रिकेट खेलना शुरू करता है, तो उसका सपना भारत के लिए खेलना होता है और आज मैंने वह सपना पूरा कर लिया है। इसलिए, मैं बहुत आभारी हूं और भगवान और परिवार का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मेरा साथ दिया और मुझे यह उपलब्धि हासिल हुई। 33 साल के सारांश का घरेलू क्रिकेट में शानदार रिकॉर्ड रहा है; उन्होंने 54 फर्स्ट-क्लास मैचों में 31.75 की औसत से 2,223 रन बनाए हैं और 27.30 की औसत से 188 विकेट लिए हैं। उन्होंने इस साल की शुरुआत में श्रीलंका के इंडिया दौरे पर भी अपनी छाप छोड़ी थी, जहां उन्होंने बल्ले से नाबाद 70 रन बनाए थे और छह विकेट लिए थे। भारत के लिए 320वें पुरुष टेस्ट खिलाड़ी बनने के अलावा, सारांश इंदौर से देश के लिए रेड-बॉल फ़ॉर्मेट में खेलने वाले पांचवें खिलाड़ी भी बन गए हैं। उनसे पहले नरेंद्र हिरवानी, राजेश चौहान,नमन ओझा और रजत पाटीदार ऐसा कर चुके हैं।

शुभमन गिल ने कोलंबो टेस्ट में रचा इतिहास

डब्ल्यूटीसी के एक संस्करण में हजार रन बनाने वाले बने पहले भारतीय कप्तान

भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो टेस्ट मैच के पहले दिन 50 रनों की पारी खेली जिसके दम पर वह एक ऐसी उपलब्धि हासिल करने में कामयाब हो गए जो अब तक कोई भी भारतीय कप्तान डब्ल्यूटीसी में करने में कामयाब नहीं हो सका था

कोलंबो,23 अगस्त 2026। भारत और श्रीलंका के बीच में खेली जा रही दो टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला कोलंबो के एसएससी ग्राउंड पर खेला जा रहा है। इस टेस्ट मैच में टॉस जीतने के बाद भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और पहले दिन का खेल खत्म होने पर भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 5 विकेट के नुकसान पर 300 रन बना लिए थे। पहले दिन के खेल में भारतीय कप्तान शुभमन गिल के बल्ले से 50 रनों की पारी देखने को मिली जिसके दम पर वह इतिहास रचने में कामयाब हो गए। गिल अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में एक संस्करण में हजार या उससे अधिक रन बनाने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं जिसमें उससे पहले कोई भी भारतीय कप्तान ऐसा करने में कामयाब नहीं हो सका था।

गिल ने सिर्फ 10 टेस्ट में पूरे किए 1000 रन

शुभमन गिल ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के संस्करण की शुरुआत बतौर भारतीय कप्तान के रूप में पिछले साल इंग्लैंड के दौरे से की थी,जिसमें अब तक उनका इस जिम्मेदारी के साथ बल्ले से काफी बेहतरीन रिकॉर्ड देखने को मिला है। गिल ने सिर्फ 10 टेस्ट मैच में अपने हजार रनों का आंकड़ा पूरा कर लिया, वहीं वह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के एक संस्करण में हजार या उससे ज्यादा रन बनाने वाले पहले भारतीय कप्तान हैं तो वहीं ऐसा करने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी हैं। इससे पहले रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे और यशस्वी जायसवाल यह कारनामा करने में कामयाब हो चुके हैं। अब तक गिल ने डब्ल्यूटीसी 2025-27 के संस्करण में अब तक 17 पारियों में 68.26 के औसत से 1024 रन बनाए हैं, जिसमें उनके बल्ले से 5 शतकीय और दो अर्धशतकीय पारियां देखने को मिली हैं।

टेस्ट में 3000 रन पूरे करने वाले गिल बने चौथे सबसे भारतीय युवा खिलाड़ी

श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो टेस्ट मैच में शुभमन गिल इस फॉर्मेट में अपने 3000 रनों का आंकड़ा भी पूरा करने में कामयाब हो गए। गिल इसी के साथ अब टेस्ट में सबसे कम उम्र में तीन हजार रन पूरे करने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं,जिसमें उन्होंने यह कारनामा 26 साल 349 दिन की उम्र में हासिल किया। भारत की तरफ से सबसे कम उम्र में टेस्ट में तीन हजार रनों का आंकड़ा पूरा करने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम पर है जिन्होंने 23 साल 228 दिन की उम्र में यह कारनामा किया था। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर 26 साल 157 दिन की उम्र के साथ वीरेंद्र सहवाग दूसरे नंबर पर है जबकि दिलीप वेंगसरकर 26 साल 263 दिन की उम्र के साथ तीसरे स्थान पर हैं।

मिचेल स्टार्क ने हासिल की बड़ी उपलब्धि

सबसे कम गेंदों में टेस्ट मैच में 10 विकेट लेने वाले बने 5वें गेंदबाज

मेलबर्न,23 अगस्त 2026।

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में जब हार का सामना करना पड़ा था तो उनकी काफी आलोचना हुई थी। इसके बाद पैट कमिंस की कप्तानी ऑस्ट्रेलियाई टीम का दूसरे टेस्ट मुकाबले में फिर से वही चैंपियन टीम वाला दबदबा देखने को मिला जिसमें वह मुकाबले को सिर्फ 2 दिनों के अंदर ही अपने नाम करने के साथ इस सीरीज को 1-1 से बराबरी पर खत्म करने में कामयाब रहे। मैके के ग्राउंड पर खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जीत में सबसे अहम भूमिका उनके स्टार बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने निभाई जिन्होंने पहली पारी में जहां 6 विकेट हासिल किए तो वहीं दूसरी पारी में 4 विकेट लेने में कामयाब रहे। इसी के साथ इस मुकाबले में स्टार्क ने अपना 10 विकेट हॉल सिर्फ 109 गेंदों में पूरा करने के साथ टेस्ट क्रिकेट में एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल कर ली।

स्टार्क 10 विकेट मैच में लेने वाले बने पांचवें सबसे तेज खिलाड़ी

मिचेल स्टार्क का बांग्लादेश के खिलाफ मैके टेस्ट की दोनों पारियों में गेंद से दबदबा देखने को मिला जिसमें उनकी गति और स्विंग के आगे बांग्लादेशी बल्लेबाज घुटने टेकते हुए नजर आए। स्टार्क ने दोनों पारियों में कुल 20 ओवर्स गेंदबाजी की तो वहीं 10 विकेट हॉल लेने के लिए उनको सिर्फ 109 गेंदों का सफर तय करना पड़ा। मिचेल स्टार्क इसी के साथ टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में किसी मैच में 10 विकेट हॉल पूरे करने वाले पांचवें सबसे तेज खिलाड़ी बन गए हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर इंग्लैंड के जॉर्ज लोहमन का नाम है जिन्होंने साल 1896 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मुकाबले में सिर्फ 91 गेंदों में अपना 10 विकेट हॉल पूरा किया था।

टेस्ट में सबसे कम गेंदों में मैच में 10 विकेट हॉल लेने वाले गेंदबाज

जॉर्ज लोहमन (इंग्लैंड) - 91 गेंद (बनाम साउथ अफ्रीका, साल 1896)

जॉनी ब्रिग्स (इंग्लैंड) - 98 गेंद (बनाम साउथ अफ्रीका, साल 1889)

जॉर्ज लोहमन (इंग्लैंड) - 103 गेंद (बनाम साउथ अफ्रीका, साल 1896)

फ्रैंक वूली (इंग्लैंड) - 104 गेंद (बनाम ऑस्ट्रेलिया, साल 1912)

बांग्लादेश ने रचा इतिहास, पहली बार टॉप-6 में शामिल

नई दिल्ली ,23 अगस्त 2026।

रविवार को ग्लोबल गवर्निंग बॉडी के हालिया अपडेट के बाद, बांग्लादेश ने आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में एक ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की। बांग्ला टाइगर्स ने पहला टेस्ट तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीता था, लेकिन दूसरा हार गए थे। इसके बावजूद, वे टेस्ट रैंकिंग में तीन पायदान ऊपर चढ़कर छठे नंबर पर पहुंच गए हैं। यह पहली बार है जब बांग्लादेश टेस्ट रैंकिंग में 9वें नंबर से ऊपर पहुंचा है। टेस्ट कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने इसे बहुत बड़ी कामयाबी बताया। ऑस्ट्रेलिया से दूसरा टेस्ट एक पारी और 51 रन से हारने के बाद शांतो ने कहा, बेशक,(छठे नंबर पर पहुंचना) अच्छी खबर है। मुझे अभी-अभी इसके बारे में पता चला है। टेस्ट रैंकिंग में छठे नंबर पर पहुंचना बहुत बड़ी कामयाबी है। अगर हम इस टेस्ट मैच में बेहतर क्रिकेट खेल पाते तो और भी अच्छा होता। बांग्लादेश वेस्टइंडीज, पाकिस्तान और श्रीलंका को पीछे छोड़कर छठे नंबर पर पहुंच गया है और अब उनकी रेटिंग 78 है। शांतो ने यह भी अपील की कि बांग्लादेश को ऑस्ट्रेलिया में और टेस्ट मैच खेलने चाहिए । उन्होंने कहा,हम 23 साल बाद यहां आए हैं (2003 के बाद ऑस्ट्रेलिया में पहली टेस्ट सीरीज)। ऐसी परिस्थितियों में इतनी अच्छी टीम के खिलाफ मुकाबला करना आसान नहीं है। अगर हम लगातार यहां आ पाते हैं, तो खिलाड़ियों को यहां खेलने का अंदाज़ा हो जाएगा।

नकली दवा पकड़ने से शुरू हुई कहानी निलंबन तक पहुंची

अब सवाल-जांच की फाइल आगे बढ़ रही है या मामला राजनीतिक चक्रव्यूह में अटका है ?

-न्यूज डेस्क-

रायपुर,23 अगस्त 2026 (घटती-घटना)। नकली दवा प्रकरण में सहायक औषधि नियंत्रक संजय कुमार नेताम के खिलाफ कार्रवाई को करीब आठ महीने का वक्त बीत चुका है,इस दौरान नकली दवा नेटवर्क की जांच आगे बढ़ी,पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया और इंदौर से रायपुर,सारंगढ़ और भाटापारा तक फैले नेटवर्क की कड़ियां सामने आईं,लेकिन संजय नेताम की विभागीय स्थिति पर अब भी वही सबसे बड़ा सवाल खड़ा है–क्या विभागीय जांच पूरी हुई? यदि हुई तो उसका निष्कर्ष क्या है? और यदि नहीं हुई तो निलंबन को अनिश्चितकाल तक खींचने की वजह क्या है? यहां एक जरूरी तथ्य यह भी है कि संजय नेताम का औपचारिक निलंबन 10 फरवरी 2026 के शासन आदेश से हुआ था,यानी 20 अगस्त 2026 तक निलंबन अवधि लगभग छह महीने की है। आठ महीने का समय मूल नकली दवा प्रकरण की शुरुआत से गिना जा रहा है,जो दिसंबर 2025 में सामने आया था। उपलब्ध सार्वजनिक रिपोर्टों में उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू होने की बात मिलती है,लेकिन उसके पूर्ण होने या संजय नेताम की बहाली का कोई स्पष्ट सार्वजनिक आदेश अब तक सामने नहीं आया है।

10 दिसंबर 2025 से शुरू हुई कहानी,जिसने पूरे विभाग को सवालों में ला खड़ा किया

इस प्रकरण की शुरुआत दिसंबर 2025 में हुई, जब रायपुर में ट्रांसपोर्ट के जरिए पहुंची संदिग्ध दवाओं की खेप ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन को सक्रिय किया, उपलब्ध घटनाक्रम के अनुसार संजय कुमार नेताम ने ट्रांसपोर्ट से संदिग्ध दवाओं की बरामदगी की,इसके बाद मामला सारंगढ़ और भाटापारा तक पहुंचा,सारंगढ़ की सरस्वती मेडिकल स्टोर और भाटापारा की प्रेम प्रकाश एजेंसी से इस खेप के तार जुड़ने की बात सामने आई, शुरुआती कार्रवाई में करीब 2.24 लाख रुपये की दवाइयां जब्त किए जाने की जानकारी सार्वजनिक हुई, बाद की कार्रवाई में बड़ी मात्रा में दवाइयों की जब्ती का मामला सामने आया,दिसंबर की कार्रवाई की रिपोर्टिंग में रायपुर और रायगढ़ के अधिकारियों द्वारा सारंगढ़ में छापेमारी का उल्लेख भी हुआ है,यानी मामला महज किसी एक मेडिकल दुकान का नहीं था,आगे की जांच ने इसे इंदौर से छत्तीसगढ़ तक फैले नेटवर्क के रूप में सामने रखा।

15 दिसंबर की टीम में ईश्वरी नारायण सिंह, नीरज साहू और राजेश सोनी-इस पूरे घटनाक्रम में निरीक्षण दल की भूमिका भी सवालों के घेरे में रही, उपलब्ध जानकारी के अनुसार 15 दिसंबर 2025 के निरीक्षण में ईश्वरी नारायण सिंह, नीरज साहू और राजेश सोनी शामिल थे,यहीं से सवालों की पहली श्रृंखला शुरू होती है–पहली कार्रवाई के बाद जब विभाग संतुष्ट नहीं हुआ तो दोबारा टीम भेजने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या पहली जांच में अपेक्षित परिणाम नहीं मिले थे? और यदि ऐसा था तो जिम्मेदारी किसकी थी?

28 जनवरी: एक मुलाकात ने पूरी दिशा बदल दी- इसके बाद आया 28 जनवरी का घटनाक्रम, संजय कुमार नेताम की सारंगढ़ प्रकरण से जुड़े व्यक्ति से रायपुर के एक रेस्टोरेंट में मुलाकात का वीडियो सामने आया, शासन के निलंबन आदेश के बारे में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार यह मुलाकात कार्यालयीन समय में हुई थी और आरोप है कि नकली दवा प्रकरण से संबंधित फाइल भी दिखाई गई,इसी आधार पर शासन ने इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम,1965 के उल्लंघन के रूप में माना,इसके बाद 10 फरवरी 2026 के आदेश से संजय कुमार नेताम को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम,1966 के नियम 9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। उनका मुख्यालय नियंत्रक,खाद्य एवं औषधि प्रशासन,नया रायपुर अटल नगर निर्धारित किया गया,यानी जिस अधिकारी के खिलाफ बाद में विभागीय कार्रवाई हुई,वही अधिकारी इस पूरे प्रकरण की शुरुआती कार्रवाई में सक्रिय भूमिका में भी था। यही विरोधाभास इस कहानी को सामान्य निलंबन प्रकरण से अलग बनाता है।

20 दिसंबर: दूसरी टीम और करीब 27 लाख की कार्रवाई

इसके बाद नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन दीपक कुमार अग्रवाल के स्तर से दूसरी टीम भेजे जाने की बात सामने आई,इस टीम में संजय कुमार नेताम,सुरेश कुमार साहू और टेकचंद धीरहे के नाम सामने आते हैं,दूसरी कार्रवाई में करीब 27 लाख रुपये की दवाइयां जब्त किए जाने की बात कही गई,इसके बाद पूर्व निरीक्षण दल से स्पष्टीकरण लिया गया,यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ...यदि एक ही प्रकरण से जुड़ी कार्रवाई में अलग-अलग अधिकारियों की भूमिका थी तो सभी के खिलाफ कार्रवाई का पैमाना समान क्यों नहीं रहा? किसी का वेतन रोका गया,किसी पर निलंबन की कार्रवाई हुई,यह अंतर अपने आप में जांच का विषय है।

15 जनवरी: नीरज साहू को टीम से हटाया गया,फिर छुट्टी में कैसे पहुंचे?

प्रकरण का सबसे दिलचस्प अध्याय भाटापारा की प्रेम प्रकाश एजेंसी से जुड़ा है,सूत्रों के अनुसार 15 जनवरी 2026 को दोबारा निरीक्षण के लिए नई टीम बनाई गई और नीरज साहू को इस बार टीम से अलग रखा गया,टीम में ईश्वरी नारायण सिंह और टेकचंद धीरहे के शामिल होने की बात सामने आई,लेकिन इसी दौरान एक और सवाल खड़ा हुआ,बताया गया कि नीरज साहू 15 और 16 जनवरी को पारिवारिक कार्यक्रम के लिए अवकाश पर थे,इसके बावजूद सूत्रों के अनुसार ईश्वरी नारायण सिंह ने उन्हें 'सहयोग' के लिए निरीक्षण में शामिल कर लिया,अब सवाल यह है कि यदि किसी अधिकारी को पहले निरीक्षण दल से हटाया गया था और वह अवकाश पर भी था,तो उसे मौके पर बुलाने की अनुमति किस स्तर से मिली? और सबसे महत्वपूर्ण...यदि वह निरीक्षण में शामिल हुआ तो क्या इसका कोई औपचारिक आदेश था? यह सवाल इसलिए और गंभीर हो जाता है क्योंकि उसी निरीक्षण से जुड़ी तस्वीरों में ईश्वरी नारायण सिंह और नीरज साहू के साथ होने की बात सामने आई और प्रेम प्रकाश एजेंसी के खाली मिलने की जानकारी भी सामने आई,व्यंग्य में कहें तो विभागीय नियमों की किताब शायद उस दिन छुट्टी पर थी...अधिकारी छुट्टी पर थे,लेकिन जांच में मौजूद थे! हालांकि यह कहना कि दुकान खाली होने के पीछे निश्चित रूप से किसी अधिकारी की भूमिका थी, बिना जांच के उचित नहीं होगा,लेकिन सूचना लीक हुई या नहीं, दुकान निरीक्षण से पहले खाली क्यों मिली और निरीक्षण दल में अवकाश पर मौजूद अधिकारी कैसे शामिल हुए–इन सवालों की जांच जरूर होनी चाहिए।

लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई अप्रैल में पकड़े गए तीन आरोपी

फरवरी में संजय नेताम के निलंबन के बाद मामला खत्म नहीं हुआ,बल्कि अप्रैल 2026 में पुलिस कार्रवाई ने नकली दवा नेटवर्क को लेकर और गंभीर तस्वीर सामने रखी,14 अप्रैल 2026 की रिपोर्ट के अनुसार रायपुर पुलिस और औषधि विभाग की संयुक्त कार्रवाई में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया,इनमें इंदौर का सप्लायर रोचक अग्रवाल,सारंगढ़ का मेडिकल स्टोर संचालक खेमराम बानी और भाटापारा का संचालक सुरेंद्र कुमार शामिल बताए गए,पुलिस के अनुसार नेटवर्क इंदौर से नकली दवाओं की सप्लाई कर स्थानीय मेडिकल दुकानों तक पहुंचाने से जुड़ा था,यह अपडेट बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि बाद की पुलिस जांच में नकली दवा का संगठित नेटवर्क सामने आया और आरोपी गिरफ्तार हुए, तो अब यह सवाल और गंभीर हो जाता है कि दिसंबर से शुरू हुई विभागीय कार्रवाई के दौरान किस स्तर पर क्या-क्या चूक हुई?

नेताम पर कार्रवाई हुई, लेकिन बाकी सवालों का क्या?

संजय नेताम के खिलाफ सरकार की कार्रवाई का अपना आधार है,शासन का कहना है कि उन्होंने कार्यालयीन समय में नकली दवा मामले के आरोपी से मुलाकात की और प्रकरण से जुड़ी फाइल दिखाई,इसलिए उनके खिलाफ निलंबन किया गया,लेकिन पत्रकारिता का सवाल यह है कि एक अधिकारी की कथित आचरण संबंधी गलती की जांच और पूरे नकली दवा नेटवर्क की प्रशासनिक जिम्मेदारी–क्या दोनों को एक ही तराजू में तौला जा सकता है? यदि नेताम दोषी हैं तो विभागीय जांच पूरी कर स्पष्ट निष्कर्ष सामने आना चाहिए,यदि वे दोषी नहीं हैं तो उन्हें बहाल किया जाना चाहिए,और यदि जांच अभी चल रही है तो विभाग को यह बताना चाहिए कि जांच किस स्तर पर है,जांच अधिकारी कौन है, आरोपपत्र जारी हुआ या नहीं और समय सीमा क्या है? निलंबन कोई अंतिम सजा नहीं है। निलंबन जांच के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा है,इसलिए अनिश्चितकाल तक किसी अधिकारी को निलंबित रखकर मामले को फाइलों में ठंडा छोड़ देना भी पारदर्शी व्यवस्था का उदाहरण नहीं माना जा सकता।

षड्यंत्र कहें या विभागी राजनीति...फैसला जांच से ही होगा

ह्यइस पूरे मामले को सीधे'षड्यंत्र'कहना फिलहाल जल्दबाजी होगी। लेकिन इसे केवल एक अधिकारी के निलंबन की सामान्य कहानी मान लेना भी उतना ही आसान निष्कर्ष होगा,क्योंकि सवाल बहुत हैं नकली दवा का नेटवर्क कौन चला रहा था? पहली जांच में क्या कमी रही? दूसरी कार्रवाई में इतनी बड़ी मात्रा कैसे सामने आई? निरीक्षण दल से हटाए गए अधिकारी अवकाश के दौरान दोबारा निरीक्षण में कैसे शामिल हुए? निरीक्षण से पहले दुकान खाली कैसे मिली? संजय नेताम की मुलाकात का पूरा संदर्भ क्या था? क्या विभागीय जांच ने इन सभी पहलुओं को एक साथ देखा? और सबसे बड़ा सवाल है की यदि अप्रैल में नकली दवा नेटवर्क के आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं,तो अगस्त तक संजय नेताम की विभागीय स्थिति पर अंतिम तस्वीर क्यों साफ नहीं हुई? यही वह सवाल है जहां मामला'निलंबन'से निकलकर विभागीय जवाबदेही का बन जाता है,नकली दवा बेचने वाला दोषी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, अधिकारी दोषी है तो जांच के बाद कार्रवाई होनी चाहिए, अधिकारी निर्दोष है तो बहाली होनी चाहिए,लेकिन यदि फाइल ही फैसला नहीं कर रही,तो फिर जनता यह मानने को मजबूर होती है कि दवा का नकली खेल तो जांच में आ गया,मगर विभागीय राजनीति की असली दवा अभी तक तैयार नहीं हुई है,अब सरकार और खाद्य एवं औषधि प्रशासन से यही अपेक्षा है कि संजय कुमार नेताम की विभागीय जांच की स्थिति,जांच अधिकारी,आरोप-पत्र, सुनवाई और वर्तमान प्रशासनिक स्थिति को सार्वजनिक किया जाए,इससे न केवल नेताम की स्थिति स्पष्ट होगी, बल्कि नकली दवा प्रकरण की पूरी कार्रवाई पर उठ रहे सवालों का भी जवाब मिलेगा।

क्या बेनी राम साहू की एंट्री महज संयोग है?

इसी पूरे घटनाक्रम के बीच बेनी राम साहू का नाम भी लगातार चर्चा में रहा,उपलब्ध जानकारी के अनुसार उनके पास खाद्य एवं औषधि प्रशासन में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां रही हैं और बाद में रायपुर लाइसेंस अथॉरिटी के प्रभार को लेकर भी उनका नाम सामने आया,यहीं से इस प्रकरण को लेकर विभागीय राजनीति की चर्चा शुरू होती है, क्या प्रभार परिवर्तन केवल प्रशासनिक जरूरत थी? क्या यह स्टाफ की कमी का परिणाम था? या फिर नकली दवा प्रकरण में घटनाओं के बीच हुए प्रशासनिक बदलावों की अलग से जांच होनी चाहिए? इन सवालों का जवाब बिना दस्तावेजी जांच के नहीं दिया जा सकता,इसलिए किसी व्यक्ति को षड्यंत्र का जिम्मेदार घोषित करना उचित नहीं होगा,लेकिन प्रभार परिवर्तन की तारीख,निलंबन की तारीख और उससे पहले हुई विभागीय कार्रवाई की पूरी टाइमलाइन सार्वजनिक होने से संदेहों का समाधान जरूर हो सकता है।

आठ महीने बाद असली सवाल यही है...जांच कहां पहुंची?

दिसंबर 2025 से अगस्त 2026 तक घटनाक्रम काफी आगे बढ़ चुका है,नकली दवा की खेप पकड़ी गई,सारंगढ़ और भाटापारा में कार्रवाई हुई,बड़ी मात्रा में दवाइयां जब्त होने की जानकारी सामने आई,संजय कुमार नेताम का नाम विवाद में आया,फरवरी में उन्हें निलंबित किया गया, अप्रैल में पुलिस ने नकली दवा नेटवर्क से जुड़े तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया,लेकिन अब भी जनता के सामने सबसे जरूरी सवाल है...संजय नेताम के खिलाफ विभागीय जांच का अंतिम परिणाम क्या है? उपलब्ध सार्वजनिक रिपोर्टों में निलंबन और विभागीय जांच शुरू होने की जानकारी तो है,लेकिन 20 अगस्त 2026 तक जांच पूरी होने या नेताम की बहाली का कोई स्पष्ट सार्वजनिक आदेश हमें नहीं मिला।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफ्सेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह*(पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)